● वर्ष-3
● अंक-49
रायपुर, गुरुवार
05 अक्टूबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

# समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› नेचुरल नहीं थी श्रीदेवी की...

### नीरज चोपड़ा ने एशियन गेम्स में रचा इतिहास

## भारत को दिलाया गोल्ड, किशोर जैना ने जीता सिल्वर

**नईदिल्ली।** भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा बुधवार को एशियन गेम्स 2023 में मैदान पर उतरे हैं। चीन के हांगझोऊ में जारी एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। वहीं भारत के ही दूसरे एथलीट किशोर कुमार जैना ने देश को सिल्वर मेडल दिलाया। लेकिन एक समय ऐसा था कि किशोर इस इवेंट में नीरज से आगे हो गए थे। इसके बाद नीरज ने वापसी करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। नीरज ने 88.88 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि किशोर ने 87.54 मीटर के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया। इस इवेंट का ब्रॉन्ज मेडल जापान के डीन रॉडरिक गेंकी ने हासिल किया। पाकिस्तान के यासिर मोहम्मद चौथे स्थान पर रहे। नीरज ने इस सीजन का अपना बेस्ट थ्रो फेंका, जबकि किशोर का ये पर्सनल बेस्ट थ्रो था।बता दें कि, नीरज ने जब अपना पहला थ्रो किया तो 87 मीटर का था, जो तकनीकी दिक्कतों के कारण रिकॉर्ड नहीं हो सका। जिसके बाद उसे रद्द करना पड़ा। उसके बाद खेल को करीब 15 मिनट तक रोका गया। नीरज काफी देर तक अधिकारियों से बात करते हुए भी दिखे थे। उसके बाद नीरज ने दोबारा थ्रो किया जो कि 82.38 मीटर का थ्रो किया जो कि पहले से काफी कम था। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने प्रयास किया जो कि थोड़ा बेहतर रहा। उन्होंने 84.49 मीटर का थ्रो किया।चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 84.49 मीटर का थ्रो किया जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं हो पाया। चौथे प्रयास में उन्होंने 88.88 मीटर का थ्रो किया। वह फिर से टॉप पर पहुंचे ये उनका सीजन का बेस्ट था। वहीं जेना ने 81.26,79.76, 86.77 और 87.54 के थ्रो फेंके। उनका पांचवां और छठा थ्रो फाउल रहा।

# देश को चला रहे हैं सिर्फ दो लोग : खड़गे

### रायगढ़ में भरोसे के सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को बताया झूठ का सरदार

**रायगढ़।** छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब सभी राजनीति पार्टियां चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर लगातार नेताओं के दौरे का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। वह भरोसे के सम्मेलन में शामिल होने रायगढ़ पहुंचे हैं। उनके साथ सीएम बघेल भी कार्यक्रम में शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में बनने वाले जैतखाम का शिलान्यास किया। यह प्रदेश के 82 चयनित विकासखण्डों में बनेगा। साथ ही नौ करोड़ आठ लाख 35 हजार रूपये की सामग्री व योजनान्तर्गत सहायता राशि शासन की विभिन्न योजना के 3088 लाभान्वित हितग्राहियों को वितरित की गई।

भरोसे का सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने संबोधन की शुरुआत जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी के साथ करते हुए कहा कि ऐसा सम्मेलन शायद देश के किसी कोने में, किसी भाग में नहीं हुआ। ये गर्व की बात है कि हर जगह भरोसे का सम्मेलन छत्तीसगढ़ में हो रहा है इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि इसका नाम भरोसे का सम्मेलन ना होकर भरोसे के अनुष्ठान का सम्मेलन हो, छत्तीसगढ़ में यह अनुष्ठान सम्मेलन बड़ी संख्या में चल रहा है। सबके हित में काम हो रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केन्द्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में सरकार दो लोग ही चलाते हैं। एक तो मोदी दूसरे अमित शाह। इनके अलावा किसी और को कुछ पता नहीं रहता कि क्या होने वाला है। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को धमकी मिलती है कि हमारी बात नहीं सुनोगे तो ईडी और आईटी के छापे पड़ेंगे। खरगे ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब-जब छत्तीसगढ़ आते हैं कांग्रेस सरकार को बदनाम करके जाते हैं। वे झूठ के सरदार हैं।

खरगे ने आगे कहा कि हमने आम लोगों की जरूरत को समझकर योजनाएं बनाई। इन योजनाओं से लाखों-करोड़ों हाथों को काम मिलता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपरीत परिस्थितियों में भी छत्तीसगढ़ के विकास का काम कभी नहीं रोका। छत्तीसगढ़ में आज चारों तरफ विकास हो रहा है। हमारी सरकार लोगों को मजबूत बनाने के लिए काम करती है। गोधन न्याय योजना से लघु उद्योगों को मजबूती मिली है। गांवों में रोजगार बढ़े हैं। अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।

मंच से खरगे ने कहा कि पांच सालों में एक लाख 75 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट योजनाओं से आम लोगों की जेब में डाले गए हैं। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में विगत पांच सालों में 40 लाख से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। खरगे ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जितना कहती है उससे ज्यादा करती है। पहले 27 जिले थे आज 33 जिले हैं, तहसीलों की संख्या भी बढ़ी है। लोगों की आमदनी बढ़ी है।

### हमारा रास्ता सत्य का रास्ता है : बघेल

सीएम भूपेश ने कहा कि कला और संस्कृति के मुख्यालय हमारे रायगढ़ में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने के बाद खरगे सबसे पहले रायपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन में आए। तबसे उनका लगाव छत्तीसगढ़ में बना रहा है। अभी हमारे मुख्य अतिथि के हाथों से बाबा गुरु घासीदास जी की आस्था के प्रतीक और गांव-गांव में निर्मित जैतखाम का शिलान्यास हुआ। सत्य के रास्ते में चलने का संदेश बाबा गुरु घासीदास जी का है। सत्य के रास्ते को महात्मा गांधी ने भी बताया। सत्य का रास्ता हमारा रास्ता है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव, नरसिम्हा राव सभी का उद्देश्य हिंदुस्तान की जनता को ताकतवर बनाने का रहा। सीएम ने कहा कि हमारा एक ही उद्देश्य रहा है कि कैसे आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सके, महिलाओं के जीवन में कैसे परिवर्तन लाया जा सके।

सीएम बघेल ने कहा कि देश का तीन चौथाई लघुवनोपज छत्तीसगढ़ में खरीदा जाता है। हमने शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से बीमा योजना शुरू की जिसका लाभ 12.50 लाख संग्राहकों को मिल रहा है। ये छत्तीसगढ़ मॉडल है, जिसमें सबसे किया वायदा हम निभाते हैं। समर्थन मूल्य में धान खरीदी, भूमिहीन मजदूरों को सात हजार रुपए प्रतिवर्ष आर्थिक अनुदान, अंग्रेजी माध्यम में नि:शुल्क शिक्षा देने का वायदा था, हमने दिया। आज छत्तीसगढ़ में किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं, बच्चे सभी को मजबूत कर रहे हैं।

# आप सांसद संजय सिंह शराब घोटाले में गिरफ्तार

**नईदिल्ली।** आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब घोटाले में ईडी की पूछताछ के बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। ईडी की तरफ से संजय सिंह के घर पर छापेमारी की गई थी। संजय सिंह की गिरफ्तारी तब हुई जब दिनेश अरोड़ा अप्रूवर बन चुके हैं। चार्जशीट में ये बताया गया था कि दिनेश अरोड़ा संजय सिंह के बहुत करीबी थे। दिनेश अरोड़ा के अप्रूवर बनने के बाद कुछ तथ्य प्रवर्तन निदेशालय को मिले थे। जिसके तहत उन्होंने सुबह से संजय सिंह के घर पर छापेमारी की। उसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है।

शराब नीति मामले में दायर आरोपपत्र में संजय सिंह का नाम था। तलाशी पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय सिंह के पिता ने कहा था कि विभाग अपना काम कर रहा है, हम उनके साथ सहयोग करेंगे। पार्टी ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी संसद में अडानी मामले को उठाने के लिए सिंह को निशाना बना रही है। शिवसेना (यूबीटी) की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा कि एनडीए में बीजेपी के एकमात्र आश्रित सहयोगी ईडी, आईटी, सीबीआई हैं।

### ईडी के अनुसार संजय सिंह पर आरोप

ईडी के आरोप पत्र के अनुसार, दिल्ली के व्यवसायी दिनेश अरोड़ा, जिन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया था, उन्होंने पहले संजय सिंह की उपस्थिति में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। एक बयान में अरोड़ा ने ईडी को बताया कि उनकी मुलाकात एक कार्यक्रम के दौरान संजय सिंह से हुई थी, जिसके बाद वह दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के भी संपर्क में आए। कार्यक्रम दिल्ली चुनाव से पहले धन जुटाने के लिए आयोजित किया गया था।

### शराब घोटाले के मुख्य सरगना हैं केजरीवाल: भाटिया

दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। भाजपा ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने साफ तौर पर कहा कि देश और दिल्ली की जनता जानती है कि शराब घोटाले के मुख्य सरगना अरविंद केजरीवाल है, उन्हीं के इशारे पर दिल्ली में ये शराब घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की साढ़ेसाती कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल पर भी असर कर रही है। आज संजय सिंह के यहां भी जांच एजेंसियों ने छापा मारा है। उन्होंने बताया कि 3 तथ्य बहुत ही चिंताजनक है- एक आरोपी दिनेश अरोड़ा ने कबूला है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर शराब कारोबारियों की एक बैठक हुई। वहां कमीशन तय हुआ।

देव दीपावली के मौके पर वाराणसी के गंगा घाटों पर बेहद शानदार और अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। इस दिन सूरज की ढलती करने के साथ में काशी के घाटों पर असंख्य दीयों को जलाया जाता है जिससे पूरा घाट जगमग होता है।

**प्रमुख समाचार**

## उज्जवला योजना: सस्ता हुआ गैस सिलेंसर

**नईदिल्ली।** दिवाली से पहले मोदी सरकार ने उज्जवला योजना के लाभार्थियों को बड़ा तोफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने उज्जवला योजना वाले सिलेंडर की सब्सिडी बढ़ाने का फैसला लिया है। इसकी जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी उन्होंने कहा, पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। हमने रक्षा बंधन और ओणम के अवसर पर रसोई गैस के सिलेंडर में 200 रुपये की कटौती करके की थी। ये कीमत घटकर 1100 से कम होकर 900 रुपये हो गई। उज्जवला योजना के लाभार्थी के 700 रुपये में गैस मिलने लगा था। उज्जवला योजना के लाभार्थी की बहनों की अब 300 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। यानि उज्जवला योजना के लाभार्थियों को अब गैस सिलेंडर 600 रुपये में मिलेंगे। दिल्ली में उज्ज्वला लाभार्थी फिलहाल 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर के लिये 703 रुपये देते हैं, जबकि इसका बाजार मूल्य 903 रुपये है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद उन्हें सिलेंडर 603 रुपये में मिलेगा।

## आरएलपी बिगाड़ेगी कांग्रेस-बीजेपी का खेल

**नईदिल्ली।** राजस्थान में भले ही विधानसभा चुनाव का समय नजदीक है, लेकिन यहां पर भी 2024 की तैयारियां होने लगी हैं। एक ओर जहां बीजेपी और कांग्रेस अकेले चुनाव मैदान में जाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं सबकी नजरें नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल पर टिकीं हैं। ऐसे में सवाल यह है कि वह भी अकेले मैदान में उतरेंगे या बीजेपी व कांग्रेस के साथ रहेंगे। निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल ने किसान हुंकार रैली के मौके पर अपनी नई पार्टी के नाम की घोषणा की थी। बेनीवाल की पार्टी का नाम %राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है और उनका चुनाव चिन्ह बोतल है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, हनुमान बेनीवाल राज्य में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को टारगेट करके चल रहे हैं। वहीं हाल ही में उन्होंने बयान दिया कि दोनों पार्टियों में काम निकालने के लिए जो जुड़ा है, वह जुड़ा रहे, लेकिन आचार संहित लगते ही अपनी तरफ वापस आ जाए। ऐसे में उन्होंने कई बड़े संकेत दिए हैं। लेकिन बेनीवाल इस दौरान किसका खेल बिगाड़ेंगे या बनाएंगे। यह समीकरण चुनाव के बाद पता चलेगा।

## टीएमसी ने केंद्रीय मंत्री पर लगाया नहीं मिलने का आरोप

**नईदिल्ली।**केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बुधवार को पश्चिम बंगाल को केंद्र द्वारा धन जारी करने के मुद्दे पर उनसे और पार्टी विधायकों से मिलने से इनकार करने के तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी के आरोपों का खंडन किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यालय कृषि भवन में धरने से बनर्जी और टीएमसी सांसदों को जबरन हटाए जाने के बाद मंगलवार रात को राजधानी में जोरदार ड्रामा हुआ। शाम छह बजे निर्धारित समय पर मंत्री के नहीं मिलने का आरोप लगाकर टीएमसी प्रतिनिधिमंडल धरने पर बैठ गया था। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का दावा था कि केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने उन्हें मिलने का समय देने के बाद भी उनसे मुलाकात नहीं की। टीएमसी के आरोपों से इनकार करते हुए मंत्री ने कहा कि मैं कल अपने निर्वाचन क्षेत्र में थी। जैसे ही मुझे जानकारी मिली कि टीएमसी सांसद मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं सब कुछ छोड़कर दिल्ली चली गयी। मैंने उन्हें शाम 6:30 बजे के लिए समय दिया था।

## अन्नामलाई की बिगड़ी तबीयत, आराम करने की सलाह

**नईदिल्ली।** तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई की एन मन एन मक्कल पदयात्रा का अगला चरण उनके खराब स्वास्थ्य के कारण पुनर्निर्धारित किया गया है। पार्टी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। पार्टी की राज्य इकाई ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर कहा कि पैदल मार्च 6 अक्टूबर को शुरू होने वाला था, लेकिन अब इसे 16 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, साथ ही बताया गया है कि डॉक्टरों ने अन्नामलाई को आराम करने की सलाह दी है। भाजपा ने चेन्नई के एक अस्पताल की विज्ञप्ति साझा कर बताया कि अन्नामलाई को ब्रोंकोस्पज्म (अस्थमा) के साथ वायरल श्वसन संक्रमण हुआ है। अन्नामलाई को दो सप्ताह तक आराम करने की सलाह दी गयी है। अन्नामलाई खांसी, सांस लेने में कठिनाई, गले में दर्द, शरीर में दर्द और थकान की शिकायत होने के बाद मंगलवार को अस्पताल गए थे। हालांकि, भाजपा ने कहा कि बृहस्पतिवार को होने वाली जिला अध्यक्षों की बैठक योजना के अनुसार होगी।

## सहयोग न करने पर व्यक्ति को नहीं कर सकते गिरफ्तार:सुको

**नईदिल्ली।** सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि प्रवर्तन निदेशालय धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत जारी समन के जवाब में असहयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने 32 पेज के विस्तृत फैसले में कहा कि 2002 के अधिनियम की धारा 50 के तहत जारी समन के जवाब में एक गवाह का असहयोग उसे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि ईडी की हर कार्रवाई पारदर्शी, बोर्ड से परे और कार्रवाई में निष्पक्षता के प्राचीन मानकों के अनुरूप होने की उम्मीद है और एजेंसी से अपने आचरण में प्रतिशोधी होने की उम्मीद नहीं है। 2002 के कड़े अधिनियम के तहत दूरगामी शक्तियों से संपन्न ईडी को अत्यंत ईमानदारी, निष्पक्षता और निष्पक्षता के साथ कार्य करते हुए देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में तथ्य दर्शाते हैं कि ईडी अपने कार्यों का निर्वहन करने में विफल रही है और इन मापदंडों के भीतर अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। निर्देश तब आया जब उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रियल्टी समूह एम3एम के निदेशकों बसंत बंसल और पंकज बंसल को जमानत दे दी।

# छत्तीसगढ़ में मोदी और शाह की प्रतिष्ठा दांव पर

**समीर चौगांवकर**

छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल इलाके बस्तर से 12 सीटें कांग्रेस के पास हैं। इसलिए भाजपा ने अपनी परिवर्तन यात्रा की शुरूआत बस्तर से ही की थी। तीन अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी भी जगदलपुर पहुंचे और परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने के साथ ही एक रैली को भी संबोधित किया। तीन महीने में प्रधानमंत्री मोदी का यह चौथा छत्तीसगढ़ दौरा था। इसके पूर्व मोदी 30 सितंबर को बिलासपुर में भाजपा की परिवर्तन यात्रा का समापन करने और उससे पहले 14 सितंबर को रायगढ़ गये थे। अपनी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उसकी नाकामियों को गिनाया। छत्तीसगढ़ में जहां अब तक के सर्वे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती दिख रही है, वहां मोदी का हमलावर होना भाजपा के लिए जरूरी भी है। असल में भाजपा हाईकमान मध्य प्रदेश में सरकार बचाने और राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को हटाने से ज्यादा बड़ी चुनौती छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने को मान रही है। छत्तीसगढ़ को अमित शाह और मोदी ने चुनौती के रूप में लिया है और इस छोटे राज्य के बड़े निर्णय खुद दिल्ली में ले रहे हैं।

भाजपा 21 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची 17 अगस्त को ही जारी कर चुकी है। उसके बाद से लगातार भाजपा संगठन बची हुई 69 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर र?हा है। एक अक्टूबर को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और संगठन

महामंत्री बीएल संतोष ने?दिल्ली में छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ बैठक की और उसके बाद शाम को केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ की दूसरी सूची पर मुहर लग गई है। यह सूची कभी भी जारी हो सकती है। छत्तीसगढ़ को लेकर अमित शाह ने विशेष रणनीति बनायी है। देश भर से 185 से ज्यादा भाजपा नेता मतदान के एक दिन पहले तक छत्तीसगढ़ में डेरा डाले रहेंगे। हर संभाग के लिए एक प्रभारी बनाया गया है। हर जिले के लिए भी एक प्रभारी बनाया गया है और हर विधानसभा सीट के लिए दो-दो प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। विस्तारक भी जमीनी स्तर पर काम देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मौजूद भाजपा के ये सभी नेता उड़ीसा, बिहार और झारखड से हैं।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 39 सीटें आरक्षित है। जिसमें से 29 सीटें एसटी वर्ग के लिए और 10 सीटे एससी वर्ग के लिए हैं। बाकी 51 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं। सीटों के हिसाब से देखें तो रायपुर संभाग से 20 सीटें, बिलासपुर संभाग से 24 सीटें, सरगुजा संभाग से 14 सीटें, दुर्ग संभाग से 20 सीटें और बस्तर संभाग से 12 सीटें आती हैं। इन पांच संभागों की जिम्मेदारी पांच बड़े नेताओं को दी गयी है। भाजपा मध्यप्रदेश की तर्ज पर जहां कोई विकल्प न हो वहां सांसद को उतारने की रणनीति पर छत्तीसगढ़ में भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरने के लिए पाटन से दुर्ग के सांसद विजय बघेल को भाजपा ने पहले ही मैदान में उतार दिया है। भूपेश बघेल और विजय बघेल पहले भी तीन बार आपस में टकरा चुके हैं जिसमें दो बार भूपेश बघेल और एक बार विजय बघेल जीत चुके हैं। भाजपा बिलासपुर संभाग पर विशेष ध्यान दे रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग बिलासपुर ही है। 8 जिलों के संभाग में यहां छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा 24 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 14 पर कांग्रेस, 7 पर भाजपा, 2 पर बसपा और एक सीट पर जनता कांग्रेस का कब्जा है। प्रदेश की 11 लोकसभा सीट में से चार लोकसभा सीट अकेले बिलासपुर संभाग से आती हैं। इसमें से तीन लोकसभा सीट पर भाजपा और एक पर कांग्रेस का कब्जा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और बिलासपुर से सांसद अरूण साव इस क्षेत्र के नेता हैं। बिलासपुर संभाग की लगभग सभी सीटों पर अनुसूचित जाति का बड़ा वोट बैक है। छत्तीसगढ़ की 10 एससी सीटों में से 4 सीटें बिलासपुर संभाग से ही हैं। यही वजह है कि बसपा के दो विधायक यहां से चुने गए है। इसलिए कांग्रेस दलित और आदिवासी वोट बैक को साधने के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जांजगीर में सभा करा चुकी है।

# खड़गे ने मुख्यमंत्री बघेल के साथ कोड़ातराई में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का किया निरीक्षण

## शासन की विभिन्न योजनाओं के 3088 हितग्राहियों को सहायता राशि व सामग्री का किया गया वितरण

**रायगढ़।** नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा व सांसद श्री मल्लिकार्जुन खरगे व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के गरिमामय उपस्थिति में रायगढ़ जिले के कोड़ातराई में आज भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्री खडगे ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ कोड़ातराई में विभागो द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टालो का निरीक्षण किया। उनके द्वारा स्टालों में हितग्राहियों से चर्चा कर विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओ का लाभ मिलने के संबंध में जानकारी ली गई। इसके साथ ही इस अवसर पर शासन की विभिन्न योजनाओ के 3088 लाभान्वित हितग्राहियों को 9 करोड़ 8 लाख 35 हजार रूपये की सामग्री व सहायता राशि वितरित की गई। इस मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय उपलब्धियों एवं योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई जिससे आमजन लाभान्वित हुए।

रायगढ़ जिले के कोड़ातराई में आयोजित भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में स्टॉल निरीक्षण के दौरान अतिथियों द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा के स्टॉल में लक्ष्मी समूह डोगीतराई के कोदो, कुटकी, रागी, बाजरा आदि मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट, तरडा रीपा के बेलमेटल मूर्तियां, संबलपुरी साड़ी, शूट पीस, शर्ट सहित अन्य प्रोडक्ट, रीपा लैलूंगा के मिट्टी बर्तन, रीपा तमनार के जुट बैग, बेकरी सामग्री, भूपदेवपुर रीपा के बांस निर्मित बंबू क्राफ्ट, स्कूल बैग और सूपा रीपा के गोबर पेंट, फिनाईल आदि अन्य उत्पाद का अवलोकन किया गया।

इसी प्रकार वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग वनमंडल रायगढ़ धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ द्वारा लघु वनोपज से बनने वाले मधुमेह नाशक चूर्ण, गुड़मार चूर्ण, हर्रा चूर्ण, आमलकी चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण सहित अन्य उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा नरवा विकास योजना, वृक्ष संपदा योजना, कृष्ण कुंज आदि को भी मॉडल बनाकर प्रदर्शित किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत लाभांवित बच्चों के पालकों द्वारा निर्मित फोटो फ्रेम मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को भेट किया गया। इसके साथ ही स्टॉल पर मुख्यमंत्री द्वारा दस सदस्यीय हरित लक्ष्मी स्व सहायता समूह सराईपाली की अध्यक्ष श्रीमती पद्मा को छत्तीसगढ़ महिला कोष के तहत एक लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया।

रेशम विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल में नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा व सांसद श्री मल्लिकार्जुन खरगे और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विभागीय सिल्क समग्र योजना से लाभान्वित कल्याणी स्व सहायता समूह की अध्यक्ष सुश्री सुमती शाह से कोसा धागाकरण कार्य से होने वाले लाभ की जानकारी ली। जिस पर सुश्री सुमती शाह द्वारा बताया गया कि इस कार्य से उनके द्वारा कोसा धागा का निर्माण किया जा रहा है। जिससे उनका जीवीकोपार्जन हो रहा है और वह लाभांवित हो रही हैं। उनके द्वारा बताया गया कि इस कार्य के माध्यम से ही उनके द्वारा अपनी लड़की की शादी और अपना जीवन बीमा कराया गया है। इसके साथ ही रेशम विभाग द्वारा स्टॉल में टसर स्पन धागा, मलबरी कोसा, टसर प्रक्षेत्र, टसर कृमिपालन आदि की प्रदर्शनी लगाई गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा हाट बाजार क्लिनिक योजना, पोषण पुनर्वास केंद्र, हमर लैब, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना, उद्यानिकी विभाग द्वारा बाड़ी योजना, फल क्षेत्र विस्तार, सब्जी क्षेत्र विस्तार तथा लोक स्वास्थ्य विभाग, मछली पालन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विभागीय गतिविधियो और योजनाओं की जानकारी दी गई।

### खड़गे व मुख्यमंत्री ने किया जैतखाम निर्माण का किया शिलान्यास

रायगढ़ के कोड़ातराई में 04 अक्टूबर को भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा व सांसद श्री मल्लिकार्जुन खडगे व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 82 चयनित विकासखण्डों में बनने वाले जैतखाम का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस.सिंहदेव, पूर्व केन्द्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, विधानसभा अध्यक्ष डॉ.चरण दास महंत, सांसद बस्तर श्री दीपक बैज, गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, उच्च शिक्षामंत्री श्री उमेश पटेल, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री गुरू रूद्र कुमार उपस्थित रहे।

# शासकीय योजना का लाभ उठाकर वर्षा गजेन्द्र ने शुरू किया पैथोलॉजी लैब

## लैब का संचालन कर अपने सपने साकार किए

**महासमुन्द।** श्रीमती वर्षा गजेन्द्र अब पैथोलॉजी लैब की संचालक के रूप में पहचानी जाती है। श्रीमती वर्षा परिवार में इस तरह के कार्यों से पहले से ही परिचित थी और ये कार्य उनकी रूचि से भी मेल खाती थी। शुरू से ही पैथोलॉजी लैब खोलने के सपने को लेकर आगे बढना चाह रही थी। लेकिन आर्थिक स्थिति आड़े आने के कारण सफल नहीं हो पा रही थी। तभी उन्हें राज्य और केन्द्र सरकार की शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए खुद के व्यवसाय के लिए ऋण योजनाओं की जानकारी मिली। उन्होंने तत्काल प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत महासमुंद स्थित कार्यालय में व्यवसाय हेतु आवेदन दाखिल किया। पैथोलॉजी लैब संचालन हेतु बैंक से 10 लाख रुपए का ऋण लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया। इस योजना के तहत ढाई लाख रुपए का अनुदान ऋण भी प्राप्त हुआ। इससे उन्हें लैब संचालन में काफी मदद मिली।

उन्होंने श्री हरि पैथोलॉजी लैब के नाम से वार्ड न. 01 शंकर नगर महासमुंद खुद का व्यवसाय शुरू किया और अपने सपने साकार किए। शुरूआत में उन्हें थोड़ी दिक्कत जरूर हुई लेकिन समय के साथ धीरे-धीरे सफलता मिलने लगी। उन्होंने बताया कि लैब मे छः महिला स्टाफ कार्य कर रही है। उन्हें लैब से बिजली बिल, बैंक की किस्त एवं लैब मे काम कर रही महिलाओं को वेतन देने के बाद नियमित आय प्रति माह प्राप्त हो रही है। जिससे उनकी घर परिवार एवं समाज में स्थिति मजबूत हुई है। आज वह अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिला रही है। साथ ही छः महिलाओं को रोजगार प्रदान कर रही है।

श्रीमती वर्षा बताती है कि जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिला। ऋण फॉर्म भरने से लेकर आवेदन का निराकरण होने तक उनका पूरा सहयोग रहा। श्रीमती वर्षा ने बताया कि किसी भी काम में उतार चढ़ाव आम बात है। हमारी दृढ़ इच्छाशक्ति प्रबल होनी चाहिए। शुरूआत में किसी भी काम में थोड़ी बहुत कठिनाई और दिक्कत अवश्य आती है। लेकिन सभी के सहयोग और मागदर्शन से उससे बाहर निकलकर आगे बढना चाहिए। वे अपने शिक्षित युवा साथियों से भी कहना चाहती है कि वे शासन की योजनाओं का लाभ उठाकर अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकते है और दूसरों को भी रोजगार देने में मदद कर सकते है। शासन की योजनाएं वास्तव में हमारे सपने साकार करने में सहायक हैं।

# चांपा में पट्टा नहीं मिलने पर चुनाव बहिष्कार की धमकी

**जांजगीर चाम्पा।** नगरपालिका क्षेत्र में शासकीय भूमि पर काबिज गरीब परिवारों ने प्रशासन से पट्टा की मांग की है।जिसे लेकर नगरवासियों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। आपको बता दें कि भूमिहीन लोगों को आवास योजना का लाभ देने के लिए जिस जगह पर वो रह रहे हैं,वहां का पट्टा जारी करने का आदेश राज्यशासन ने दिया है। लेकिन राज्य सरकार की इस योजना का फायदा चांपा नगर पालिका के वार्ड नंबर 1,2,3 और 4 के गरीब परिवारों को नहीं मिल पा रहा है। इन वार्डों में रह रहे लोगों ने लंबे समय से पट्टा की मांग की है। सभी जरुरी दस्तावेज जारी करने के बाद भी परिवारों को पट्टा नहीं मिला।

इस घटना के बाद कुछ कांग्रेसी नेता समर्थकों के साथ एसडीएम दफ्तर आए।जहां कांग्रेसियों ने एसडीएम पर जान बूझकर पट्टा देने में लेट लतीफी करने का आरोप लगाया।साथ ही साथ कहा कि अधिकारी पट्टा देने में लेट कर रहे हैं,जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

कांग्रेस नेता राजेश अग्रवाल ने कहा एसडीएम सिर्फ टीम गठित करके सर्वे कराने की बात कह रहे हैं।ऐसा लग रहा है कि आचार संहिता लग जाएगा।फिर पट्टा नहीं बट पाएगा।ऐसे में कांग्रेस सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है।

विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत से गरीब परिवारों ने मुलाकात की थी।इसके बाद चरणदास महंत ने एसडीएम को तीन दिन के अंदर पट्टा जारी करने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके अफसरों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी।कांग्रेस नेताओं के आश्वासन के बाद भी जब परिवारों को पट्टा नहीं मिला तो सभी ने एसडीएम दफ्तर का घेराव कर

दिया।वहीं पट्टा नहीं मिलने से आक्रोशित महिलाओं ने आचार संहिता लगने से पहले पट्टा नहीं मिलने पर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है।

वार्डवासी शांतिबाई ने कहा हम लोग कई सालों से पट्टा की मांग कर रहे हैं।नेताओं के निर्देश के बाद भी पट्टा नहीं मिला। यदि चुनाव से पहले पट्टा नहीं मिला तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे।

वहीं इस बारे में एसडीएम का कहना है कि पट्टा देने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। चार टीम गठित कर दी गई है। रिपोर्ट आने के बाद पट्टा दिया जाएगा। एसडीएम नीर निधि नंदेहा ने कहा पूर्व में कई पट्टा वितरण के दौरान बड़ी गलती हुई थी। जिसे रोकने के लिए पारदर्शिता के साथ सर्वे कराया जा रहा है।सर्वे रिपोर्ट के बाद पट्टा बांट दिया जाएगा।

आपको बता दें कि पट्टा वितरण योजना से सरकार को उम्मीद है कि चुनाव में उन्हें फायदा होगा।लेकिन जिन जगहों पर अब तक पट्टा नहीं बंट पाया है वहां जनता मूड सरकार को लेकर थोड़ा बदल भी सकता है।

# पंडरिया में बैगा आदिवासियों से मिले सिंहदेव, साथ मिलकर खाया खाना

**पंडरिया।** छत्तीसगढ़ में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं नेताओं का आम लोगों से मिलने का दौर भी बढ़ गया है। इसी कड़ी में प्रदेश के डिप्टी सीएम सिंहदेव पंडरिया के बैगा आदिवासियों से मिले। अपने बीच राजा साहब को देखकर आदिवासी काफी खुश हो गए। आदिवासियों ने कहा कि ऐसा लगा जैसे भगवान उतर कर आ गए।

पंडरिया ब्लॉक के वनांचल क्षेत्र के पहाड़ों पर स्थित झूमर गांव में जैसे ही टीएस सिंहदेव पहुंचे। वहां के बैगा आदिवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी ने सिंहदेव को बिरनमाला पहनाकर स्वागत किया। आदिवासी समाज के लोगों ने अपने देवता नाग व नागिन बाबा की फोटो उन्हें भेंट की। इस दौरान वहां तेज हवाएं शुरू हो गई। बावजूद इसके टीएस ने आदिवासी महिलाओं की समस्याएं सुनी और उन्हें जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। सिंहदेव ने आदिवासियों के साथ भोजन भी किया। जमीन पर बैठकर पतरी में कुटकी और चेच भाजी के साथ आदिवासी खाने का मजा लिया।

रामली बैगिन ने कहा हमारे साथ खाना खाए, हमें बहुत अच्छा लगा। इस जंगल में पहली बार कोई उड़ने वाले डोंगी से पहुंचे। ऐसा लगा जैसे भगवान उतर कर आए हैं। हमारी समस्याओं को सुने और उसे दूर करने की बात कही है। उन्होंने जगन्नाथ पुरी और समुंद्र घुमाने की बात भी कही।

हफ्ते भर में कांग्रेस की लिस्ट होगी जारी- टीएस सिंहदेव के पहुंचने पर पंडरिया विधानसभा टिकट के दावेदार भी पहुंच गए। पैराशूट प्रत्याशी को टिकट देने के मीडिया के सवाल पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि काम करने वाले और जिताऊं उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस की लिस्ट पर मंत्री ने कहा कि कांग्रेस हफ्ते भर में लिस्ट जारी कर देगी।

**छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार**

### रेत का अवैध उत्खनन व परिवहन करते ट्रैक्टर जब्त

**कोरबा।** जिले के कोरबी सर्किल में वन्य क्षेत्र में स्थित एक नाले से रेत का अवैध उत्खनन व परिवहन करते एक ट्रैक्टर को वन विभाग की टीम ने जब्त कर भारतीय वन अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार वन विभाग के अधिकरियों को सूचना मिली थी कि वनमंडल कटघोरा के केंदई रेंज अंतर्गत कोरबी सर्किल में कक्ष क्रमांक पी.346 में स्थित गागा नाला से कुछ लोगों द्वारा रेत का अवैध उत्खनन व परिवहन किया जा रहा है। इस सूचना पर रेंजर अभिषेक दुबे के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने सोमवार की शाम जब नाले में दबिश दी तो मौके पर एक स्वराज ट्रैक्टर मिला जिसमें कुछ लोग रेत का उत्खनन कर उसे भर रहे थे। उन्हें पकड़कर जब टीम द्वारा रेत के उत्खनन तथा परिवहन संबंधी दस्तावेज देने को कहा तो वे प्रस्तुत नहीं कर सके। वन विभाग की टीम को पूछताछ में वाहन चालक ने अपना नाम समार साय पिता बालकराम गोंड़ निवासी ग्राम लाद तथा ट्रैक्टर मालिक का नाम अश्वनी जायसवाल बताया जो कोरबी के रहने वाले हैं।

### बस्तर जिले के 75 पंचायतों में लगेगा हाई मास्क लाइट

**जगदलपुर।** बस्तर जिले के 75 ग्राम पंचायतों में हाई मास्क लाइट लगाए जाने की योजना है। इसके लगने से जान व माल की नुकसान कम होगा और जनजीवन सामान्य होगा। गांव के भीतर प्रमुख चौक-चौराहों अथवा मुख्य मार्ग पर हाई मास्क लाइट लगाई जाएगी। क्रेडा विभाग की ओर से ऐसे 75 गांव की सूची तैयार की गई है, जिसके लिए स्वीकृति मिली है। इससे गांव के चौराहों में पर्याप्त रोशनी उपलब्ध हो पाएगी, सोलर प्लेट के द्वारा संचालित होने पर बिजली का खर्च भी बचेगा। चौक-चौराहों पर चलह-पहल बढ़ेगी, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने सुविधा होंगी। साथ ही चौराहों पर रात के अंधेरे में होने वाले हादसे भी कम होंगे। इसके चलते पंचायत को बिजली बिल के झंझट से मुक्ति मिलेगी। फिलहाल सेमरा पंचायत में हाई मास्क लाइट स्थापित किया गया है, इसके साथ ही अन्य पंचायतों में भी स्थापित करने का कार्य किया जाएगा।

### भाजपा की सरकारों ने लाया गरीब के जीवन मे बदलाव

**नगरी।** सिहावा विधानसभा के सियारी नाला शक्ति केंद्र में आयोजित बैठक मे स्थानीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा जिला महामंत्री कविन्द्र जैन ने कहा कि केंद्र मे अटल जी की सरकार और उसके बाद नरेन्द्र मोदी की सरकार ने तथा राज्य मे डॉ रमन सिंह की सरकार ने देश के हर वर्ग के जीवन मे बदलाव लाने का काम किया । चाहे खाद्य सुरक्षा हो, पक्का आवास हो, स्वास्थ्य बीमा हो या फिर सड़क, बिजली, पानी की सुविधा हो, भाजपा की सरकारों ने ही अंतिम पंक्ति मे बैठे व्यक्ति की सुख सुविधा की चिंता की है । न केवल अपने जीवन मे खुशिहाली के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए भाजपा की सरकार केंद्र और राज्य मे बनाना आवश्यक है। कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार, अपराध और वादखिलाफ़ी की है। जिला उपाध्यक्ष अरविंदर मुंडी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता अब राज्य मे बदलाव चाहती है। गोबर से लेकर शराब तक राज्य मे सिर्फ घोटालों की सरकार है। वृद्धावस्था पेंशन हो या विधवा पेंशन या फिर बेरोजगारी भत्ता सभी मामलों मे भूपेश ने छलने का काम किया।

### नवाखाई पर्व समाज में सद्भाव की पहचान है : डॉ. लक्ष्मी ध्रुव

**नगरी।** सिहावा विधानसभा के विधायक डॉ लक्ष्मी ध्रुव के द्वारा गोड़वाना समाज उपक्षेत्र कसपुर एवं उपक्षेत्र बरबांधा के ग्राम आमगांव द्वारा आयोजित नवाखाई मिलन समारोह में शामिल हुई। नवाखाई मिलन समारोह आदिवासी गोंडवाना समाज उप क्षेत्र कसपुर द्वारा नवाखाई मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 14-15 गांव के समाजजन शामिल हुए। जहां अतिथियों प्रमुखों व पदाधिकारियों का पगड़ी पहना व महुआ फूल से बना माला पहनाकर स्वागत किया। समाज के सभी प्रभाग के पदाधिकारियों का एवं मुख्य अतिथि डॉ लक्ष्मी ध्रुव का भव्य स्वागत सम्मान किया समाज की ओर से अपने सांस्कृतिक नृत्य रेला पाटा मांदरी टुटकली एवं रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुती दी। नवाखाई पर्व समाज की परंपरा अनुसार सदियों से मनाया जा रहा है। इसमें नए फसल के आने पर ईष्टदेव को धन्यवाद ज्ञापित करते है। डॉ लक्ष्मी ध्रुव ने कहा सामाजिक परंपराओं का निर्वहन करना हम सभी की जिम्मेदारी है तथा त्योहारों के माध्यम से समाज में एकता बनी रहती है।

### समता मूलक समाज की स्थापना ही राम राज्य की स्थापना है : शशि पवार

**धमतरी।** भारतीय जनता पार्टी के नेता बस्ती संपर्क अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत गाँव गाँव और वार्ड वार्ड जाकर लोगों से मिलकर उन्हे केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे और भाजपा के लिये समर्थन जुटाने मे लगे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत धमतरी विधानसभा के अंतिम गाँव ग्राम मड़वापथरा मे जिलाध्यक्ष शशि पवार, कविन्द्र जैन एवं अरविंदर मुंडी ने ग्रामीणों की बैठक ली तथा घर घर जाकर छग की कांग्रेस सरकार के खिलाफ तैयार किये गये आरोप पत्र का वितरण किया साथ ही भाजपा द्वारा कराये गये विकास कार्यों की भी जानकारी दी। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष शशि पवार ने कहा कि देश और प्रदेश मे राम राज्य केवल भाजपा की सरकार ही ला सकती है। समता मूलक समाज की स्थापना ही रामराज्य की स्थापना है और भाजपा समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार दिलाने के लिये साधन के रूप मे सत्ता का उपयोग करती आयी है।

# समाज के विकास में अधिवक्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान : बघेल

- **जिला न्यायालय परिसर में 2 करोड़ 52 लाख रूपए की लागत के विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन**

**दुर्ग।** मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के अधिवक्ताओं को बड़ी सौगातें दी है। उन्होंने दुर्ग प्रवास के दौरान जिला न्यायालय परिसर में 33 लाख रूपए की लागत से निर्मित अधिवक्ता संघ के आदर्श लाइब्रेरी का लोकार्पण तथा 2 करोड़ 19 लाख रूपए की लागत से बार रूम नंबर 04 की पुरानी बिल्डिंग के नये सिरे से निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एडव्होकेट जनरल श्री सतीश चंद्र वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि शपथ ग्रहण के समय अधिवक्ता संघ द्वारा लाइब्रेरी एवं बार रूम मरम्मत की मांग की गई थी। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ में न्यायालयीन व्यवस्था से जुड़ी व्यवस्था संबंधी विभिन्न मांगे पूरी की गई है। उन्होंने देश की आजादी में अधिवक्ताओं की योगदान को उद्धृत करते हुए कहा कि समाज के विकास हेतु तब भी अधिवक्ताओं का योगदान रहा और आज भी है। आज समाज में सबसे ज्यादा बुद्धिजीवियों में अधिवक्ताओं को माना जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के संविधान में व्यवस्था है कि यदि आप आरोपी है, तो को भी आपको कानून सम्मत अपनी बाते रखने का अवसर मिलता है। मुख्यमंत्री ने न्यायालयीन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अधिवक्ताओं के योगदान के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एडव्होकेट जनरल श्री सतीश चंद्र वर्मा ने अपने उद्बोधन में न्यायालयीन व्यवस्था में आवश्यकताओं के लिए मुख्यमंत्री जी की पहल पर प्रकाश डाला। अधिवक्ता संघ की अध्यक्ष सुश्री नीता जैन ने स्वागत प्रतिवेदन में संघ की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने पर मुख्यमंत्री जी को संघ की ओर से साधुवाद दिया। समारोह में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीता यादव एवं अन्य न्यायाधीश, जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं अधिवक्तागण, विधायक श्री अरूण वोरा एवं देवेन्द्र यादव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के श्री आर.एन. वर्मा, नगर निगम दुर्ग के महापौर श्री धीरज बाकलीवाल उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज गंजपारा दुर्ग में नवनिर्मित आर्गेनिक सी-मार्ट के प्रवेश द्वार पर फीता काटकर इसका अवलोकन किया। 67 लाख रूपए की लागत से निर्मित इस आर्गेनिक सी-मार्ट में किसानों द्वारा उत्पादित आर्गेनिक उत्पादकों की बिक्री की व्यवस्था की गई है। ज्ञात हो कि जिले में कुल 155 जैविक बाडियां है, जिसमें 60 जैविक बाडियों में साग-सब्जी-फल का उत्पादन हो रहा है। जिले में पंजीकृत 1200 किसान जैविक खेती कर रहे हैं। सी-मार्ट के आरंभ हो जाने के पश्चात् इन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है। सी-मार्ट के माध्यम से अब तक एक करोड़ 78 लाख रूपए की जैविक उत्पादों की बिक्री हो चुकी है।

# गिरदावरी की आड़ में की जा रही है अवैध वसूली : ननकीराम

**कोरबा।** रामपुर क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने धान फसल की गिरदावरी में बड़े स्तर पर गड़बड़ी करने और किसानों से अवैध रूप से पैसों की उगाही करने का आरोप लगाया है।

विधायक ने बताया कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र के चारमार, मदवानी और नोनदरहा गांव के किसानों के धान की फसल के खेतों का रकबा में बिना गिरदावरी किये कटौती कर दिया गया है। हल्का नम्बर 35 की पटवारी श्रीमती ममता सिंह अब रकबा जोड़ने के लिए रुपयों की मांग कर रही है।

उन्होंने बताया कि उक्त तीनों गांव के किसानों ने मामले की लिखित शिकायत उनसे की है। किसानों ने काट गए धन का रकबा तुरन्त जोड़ने और पटवारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि मामले की शिकायत कलेक्टर कोरबा और जिला पुलिस अधीक्षक से भी की गई है।

कद्दावर आदिवासी नेता और भाजपा विधायक कंवर ने कलेक्टर से संबंधित पटवारी पर तुरन्त कड़ी कार्रवाई करने और किसानों की खरीफ फसल का रकबा में सुधार करने की मांग की है। विधायक ने इस सम्बंध में पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर पटवारी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की है। उन्होंने संबंधित पुलिस थाना प्रभारी को भी घटना की जानकारी दी है और पटवारी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस कार्रवाई नहीं करते हैं तो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी।

जानकारी के अनुसार यह शिकायत सम्पूर्ण कोरबा जिले के किसानों को है। लेकिन कोई भी किसान पटवारी या राजस्व विभाग के अफसरों से लड़ना नहीं चाहते। इसीलिए शिकायतें सामने नहीं आ रही हैं।

## संक्षिप्त समाचार

### हिन्दू-मुस्लिम करके वैमनस्यता फैलाने का काम कांग्रेस ही करती आई है : चंद्राकर

**रायपुर।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ओबीसी, अजा, अजजा के साथ भेदभाव करने के आरोप को झूठ का पुलिंदा बताते हुए भाजपा मुख्य प्रवक्ता व पूर्व मंत्री श्री अजय चंद्राकर ने कहा कि वास्तविकता क्या है, यह जनता के सामने है। कांग्रेस नेताओं को भारत के इतिहास को अच्छी तरह पढऩा चाहिए। इतिहास गवाह है कि हिन्दू-मुस्लिम करके वैमनस्यता फैलाने का काम कांग्रेस ही करती आई है। मुस्लिमों को वोट बैंक समझने वाली कांग्रेस की सच्चाई मुस्लिम समुदाय भी अब भलीभाँति जान चुका है। केंद्र सरकार का तो मूलमंत्र ही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। श्री चंद्राकर ने पिछले 70 सालों से बस्तर को छलने और अंधेरे में रखने वाली कांग्रेस सरकार भाजपा के 15 साल के सुशासन और बस्तर के आदिवसियों का विकास देखकर तिलमिलाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही है। जब बस्तर के लोगों के सर्वांगीण विकास करने का प्रधानमंत्री श्री मोदी ने संकल्प लेने की बात कही, तो कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज अनर्गल, झूठे आरोप लगाकर छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

### दो करोड़ तीन लाख 60 हजार 240 मतदाता करेंगे मतदान

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर बुधवार को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने अंतिम मतदाता सूची जारी करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में दो करोड़ तीन लाख 60 हजार 240 मतदाता मतदान करेंगे। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में पत्रकार-वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार-वार्ता में बताया कि प्रदेश में निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद आज सभी मतदान केंद्रों में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। आज प्रकाशित सूची के अनुसार राज्य में कुल दो करोड़ तीन लाख 60 हजार 240 मतदाता हैं। इनमें एक करोड़ एक लाख 20 हजार 830 पुरूष मतदाता, एक करोड़ दो लाख 39 हजार 410 महिला मतदाता और 790 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद राज्य में सात लाख 19 हजार 825 मतदाता बढ़े हैं। इससे पहले 28 सितंबर तक दावा आपत्तियों का निराकरण किया गया।

### मुख्यमंत्री का छग लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों के हित में बड़ा फैसला

**रायपुर।** मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए आयोग की परीक्षाओं के दस्तावेज के विनिष्टिकरण की व्यवस्था में बदलाव लाने के निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में राज्य शासन द्वारा लोक सेवा आयोग को आयोग की परीक्षाओं की आंसर सीट एवं दस्तावेजों के विनिष्टिकरण के अवधि को दो साल किए जाने का प्रस्ताव भेजा है। गौरतलब है कि पीएससी परीक्षाओं की आंसर सीट एवं दस्तावेज के विनिष्टि किए जाने के कायदे कानून छत्तीसगढ़ राज्य में लंबे समय से चली आ रही है। इसमें बदलाव लाने के लिए मुख्यमंत्री ने आवश्यक निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा लोक सेवा आयोग को आंसर सीट एवं अन्य दस्तावेजों को विनिष्टिकरण की अवधि को दो साल तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव भेजा गया है।

### पर्यवेक्षक के रिक्त पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन 10 अक्टूबर से

**रायपुर।** महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों के लिए व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर जारी चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों के अभिलेखों एवं दस्तावेजों का सत्यापन 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक किया जाएगा। सत्यापन का कार्य नवा रायपुर, अटल नगर में इन्द्रावती भवन के ब्लॉक-1, द्वितीय तल स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालनालय के मिटिंग हॉल क्रमांक 02 एवं 04 में सुबह 10 बजे से किया जाएगा।

# कांग्रेस अध्यक्ष ने करोड़ों की योजनाओं की दी सौगात

■ रायगढ़ में भरोसे के सम्मेलन में शामिल हुए मल्लिकार्जुन खड़गे

**रायगढ़।** कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायगढ़ में भरोसे का सम्मेलन में पहुंचे। कोड़ातराई में भरोसे का सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम भूपेश बघेल प्रदेश के 3088 हितग्राहियों को 9 करोड़ 8 लाख 35 हजार रुपये की सहायता राशि की सौगात दी। छत्तीसगढ़ के 82 ब्लॉक में बनने वाले जैतखाम का शिलान्यास भी हुआ। सरकारी विभागों की उपलब्धि और योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई।

भरोसे के सम्मेलन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के तहत 539 स्वसहयता समूहों को 80 लाख 45 हजार रुपए की राशि दी गई। 1189 समूहों को 7 करोड़ 13 लाख 40 हजार रुपए की सामुदायिक निवेश राशि भी दी गई। श्रम विभाग की मिनीमाता महतारी जतन, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक औजार सहायता योजना समेत विभिन्न योजनाओं के 1317 हितग्राहियों को 98 लाख 71 हजार रुपए की सामग्री बांटी गई।

शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत दिलकुंवर राठिया को 4 लाख और उर्मिला राठिया को 2 लाख रुपए की राशि दी गई। किसान समृद्धि योजना के तहत 3 लाख 79 हजार रुपए की लागत से 13 हितग्राहियों को नलकूप खनन एवं अनुदान, राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन योजना के तहत पंप सेट दिया गया। समाज कल्याण विभाग की सहायक उपकरण योजना के तहत ट्रायसाइकिल, टीएलएम और ब्लाइन्ड स्टिक सहायक उपकरण के साथ ही छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना के तहत 9 हितग्राहियों को 6 लाख रुपए दिए गए।

भरोसे का सम्मेलन में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों से न सिर्फ किसान बल्कि सभी वर्ग के लोगों को फायदा हुआ है। रायगढ़ में पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बिके हैं। भूमिहीन किसानों के लिए कोई योजना नहीं थी, लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार भूमिहीन किसानों की भी मदद कर रही है। उमेश पटेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया खेल को आगे बढ़ाने का काम भूपेश बघेल सरकार ने किया है। हमारी छत्तीसगढ़िया संस्कृति, खानपान को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों से सभी वर्ग के लोगों को फायदा हुआ है। भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़िया संस्कृति, खानपान को आगे बढ़ाने का काम किया है।

विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा आज प्रधानमंत्री की 14 सितंबर को हुई सभा से ज्यादा भीड़ जुटी है। यहां जुटी भीड़ यह बताने के लिए काफी है कि जनता को कांग्रेस पर कितना भरोसा है।

पीसीसी चीफ दीपक बैज हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार पर सभी वर्गों का भरोसा है, इसलिए भरोसे का सम्मेलन किया जा रहा है। ईडी आईटी से भाजपा हमें डराना चाहती है। छत्तीसगढ़ को मणिपुर और हरियाणा बनाकर जलाना चाहते हैं। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के विकास की बात करेगा वही छत्तीसगढ़ में राज करेगा।

टीएस सिंहदेव ने मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके रायगढ़ दौरे के दौरान कुछ बात ऐसें हुईं जिसका भरपूर राजनीतिक उपयोग किया गया, शिष्टाचार का भरपूर राजनीतिकरण हुआ। सिंहदेव ने पीएम मोदी पर धान खरीदी पर भी झूठ बोलने का आरोप लगाया।

छत्तीसगढ़ सरकार न्याय की बात करती है। जगदलपुर में पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार धान खरीदती है। यदि वो धान खरीदते हैं तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि साल 2014 में जब रमन सिंह की सरकार थी तो बोनस बंद क्यों कराया। मोदी लगातार झूठ बोल रहे हैं। भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि गुजरात में 5 साल में 11 करोड़ 81 लाख देकर लघु वनोपज खरीदी गई। वहां 5 साल में 15 करोड़ की वनोपज खरीदी गई। लेकिन छत्तीसगढ़ में 388 करोड़ की वनोपज खरीदी गई। तेंदूपत्ता की सबसे ज्यादा कीमत छत्तीसगढ़ में मिलती है। हमारी सरकार ने महेंद्र कर्मा के नाम से बीमा की व्यवस्था भी शुरू की। रायगढ़ में आकर मोदी गोधन योजना को लेकर भी झूठ बोलकर गए हैं।एक तरफ गुजरात मॉडल है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ मॉडल है। हमारे मॉडल में जो कहा जाता है, वह वादा पूरा किया जाता है

कांग्रेस अध्यक्ष के जिंदल एयरपोर्ट पहुंचने पर सीएम भूपेश बघेल ने उनका स्वागत किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी खड़गे का स्वागत किया। कोड़ातराई पहुंचने के बाद खड़गे और सभी नेताओं ने सभा स्थल में लगाए गए अलग अलग स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया।

### इससे पहले कब कब पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे

28 सितंबर को खड़गे बलौदाबाजार के कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। जहां कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी और केंद्र पर कई आरोप लगाए। खड़गे ने कहा था कि मोदी जी महिलाओं को आरक्षण न आज देंगे, न ही 2029 में देंगे। खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार को जुमलों की सरकार बताया था। उससे पहले राजनांदगांव में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में खड़गे शामिल हुए। जांजगीर चांपा में भरोसे के सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले खड़गे नवा रायपुर में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए थे।

## निगम सभापति दुबे ने किया एक करोड़ की लागत से होने वाले कार्यों का भूमिपूजन

**रायपुर।** पं. भगवती चरण शुक्ल वार्ड में लगभग एक करोड़ की लागत से होने वाले विभिन्न कार्यों का बुधवार को नगर निगम के अध्यक्ष प्रमोद दुबे ने भूमि पूजन किया। विभिन्न स्थानों पर पेवर लगाने सहित विविध सौंदर्यीकरण के कार्य के लिए लगभग 1 करोड़ रूपये की लागत से शीघ्र करवायें जायेंगे।

वार्ड के छत्तीसगढ़ कॉलेज के समीप लगभग 98 लाख रूपये की लागत से गन्दे पानी की निकासी के सुगम प्रबंधन हेतु नए नाले का निर्माण अधोसंरचना मद से होगा। नगर पालिक निगम रायपुर के सभापति जोन 4 पदेन अध्यक्ष, वार्ड 57 के पार्षद प्रमोद दुबे ने वार्ड पार्षद प्रतिनिधि बाकर अब्बास सहित वार्ड के वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, गणमान्य जनों, सामाजिक कार्यकर्तृताओं, नवयुवकों के साथ मिलकर श्रीफल फोड़कर एवं कुदाल चलाकर पण्डित भगवती चरण शुक्ल वार्ड क्रमांक 57 के अंतर्गत आने वाले विभिन्न चौक-चौराहों एवं चबूतरों में आवश्यक सुधार एवं मरम्मत सहित उनके जीर्णोद्धार के कार्य 9 लाख 95 हजार रूपये, विभिन्न सामुदायिक भवनों की आवश्यक मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के कार्य 7 लाख 49 हजार रूपये, कुंदरापारा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य 10 लाख 21 हजार रूपये, फरिश्ता अपार्टमेंट, पेंशनबाड़ा एवं कुंदरापारा में जीपीएस एवं विकास के कार्य 5 लाख 23 हजार रूपये, पेंशनबाड़ा एवं शैलेन्द्र नगर में नाली, पुलिया निर्माण 10 लाख रूपये, काली माता मन्दिर के समीप सौंदर्यीकरण का कार्य 1 लाख रूपये, उत्कल बस्ती कुंदरापारा में शेड का निर्माण 2 लाख रूपये, ईदगाह बैरन बाजार के समीप निर्माण कार्य 2 लाख रूपये, हिन्दू हाईस्कूल पेंटिंग, सुधार, मरम्मत एवं शौचालय निर्माण कार्य 3 लाख 27 हजार रूपये की लागत से करवाने भूमिपूजन हुआ । नगर निगम जोन 4 जोन कमिश्नर राकेश शर्मा एवं कार्यपालन अभियन्ता पद्माकर श्रीवास को तत्काल स्वीकृति अनुसार वार्ड 57 में नए विकास एवं निर्माण कार्य स्थलों पर प्रारम्भ करवाने एवं सतत मॉनिटरिंग करते हुए तय समयसीमा के भीतर विकास कार्यों को जनहित में जनसुविधा विस्तार हेतु पूर्ण करवाया जाना प्राथमिकता से सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिये।

## शराब को लेकर झूठ बोलकर अपनी जिम्मेदारी से मुँह चुरा रही : चंदेल

■ भाजपा पर शराब बेचने की ट्रेनिंग देने के आरोप पर नेता प्रतिपक्ष जमकर बरसे

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने शराब को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगातार झूठ बोलकर अपनी जिम्मेदारी से मुँह चुराने का आरोप लगाया है। चंदेल ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल द्वारा भाजपा की पूर्ववर्ती राज्य सरकार पर शराब बेचने की ट्रेनिंग देने का आरोप लगाया जाना उस कहावत को चरितार्थ कर रहा है कि सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसमें बहत्तर छेद! अपनी वादाखिलाफी और शराब घोटाले के काले कारनामों को ढँकने के लिए लाख झूठ बोलकर, स्तरहीन बयान देकर भी मुख्यमंत्री बघेल छत्तीसगढ़ को शराब के दलदल में धकेलने के पाप से बरी नहीं हो पाएंगे।

चंदेल ने कहा कि प्रदेश साक्षी है कि पूर्ण शराबबंदी का वादा करने के बावजूद प्रदेशभर में गाँव-गाँव, गली-गली और घर-घर शराब पहुँचाने का कलंकित अध्याय मुख्यमंत्री बघेल के शासनकाल में लिखा जा रहा है। शराब की प्रीमियम दुकानें चल रही हैं, नकली होलोग्राम बनाए जा रहे हैं और गंगाजल की कसम खाकर माँ गंगा तक को अपमानित करने का कृत्य कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। यहाँ तक कि कोरोना काल तक में तमाम वर्जनाओं और मर्यादाओं को ताक पर रखकर भूपेश सरकार ने शराब बेचने की ऐसी लोलुपता दिखाई कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ शर्मसार हो गया। षड्यंत्र की इन्तेहा देखिए कि खुद सरकार से जुड़े लोग कच्ची और देशी शराब बिकवाते थे और जब इसे पी कर बड़ी संख्या में मौतें हुई तो इसे ही बहाना बनाकर भूपेश सरकार ने शराब की होम डिलीवरी भी शुरू कर दी थी। ऐसा अन्याय करने वाली भूपेश बघेल सरकार इस देश की पहली ऐसी राज्य सरकार है। मुख्यमंत्री बघेल प्रदेश को यह जवाब दें कि क्या गंगाजल की सौगंध खाकर पूर्ण शराबबंदी का वादा करते समय कांग्रेस ने शराबबंदी के लिए ऐसी कोई शर्त रखी थी? भूपेश सरकार के आबकारी मंत्री कवासी लखमा को तो यहाँ तक कहते पूरे प्रदेश ने सुना-देखा है कि जब तक मैं सरकार में हूँ, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं होगी।

## ध्वनि प्रदूषण की हो प्रभावी रोकथाम: जैन

**रायपुर।** मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम संबंध में पारित आदेश के पालन में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के

निर्देश दिये गये। बैठक में वाहनों में तेज आवाज में बजाने वाले डीजेस और एम्पलीफायरर्स पर त्वरित आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि ध्वनि प्रदूषण अधिनियम का उलंघ्घन करने वालों पर सक्त कार्यवाही की जायें। मुख्य सचिव ने राज्य के सभी कमिश्नरों, आई.जी, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को जनहित में ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। मुख्य सचिव ने ध्वनि प्रदूषण के प्रभावी रोकथाम के लिए सभी जिलों में लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश अधिकारियों को दिये । बैठक में डी.जी.पी श्री अशोक जुनेजा मौजूद थे। ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए रात्रि 10 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक डीजे बजाना पूर्णत: प्रतिबंधित हो यह सुनिश्चित होना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहनों और ध्वनि विस्तारक यंत्रों को जब्त किया जाये इस संबंध में सभी जिलों में पुलिस, राजस्व और पर्यावरण विभाग की टीम गठित कर ध्वनि प्रदूषण को रोकने समन्वय से कार्यवाही की जाये।

# हमारा एक ही उद्देश्य रहा है कि कैसे आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सके : मुख्यमंत्री

■ ये छत्तीसगढ़ मॉडल है, जिसमें सबसे किया वायदा हम निभाते हैं

**रायगढ़।** रायगढ़ में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में आम जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि कला और संस्कृति के मुख्यालय हमारे रायगढ़ में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खडगे जी आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने के बाद खड़के की सबसे पहले रायपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन में आए। तबसे उनका लगाव छत्तीसगढ़ में बना रहा है। अभी हमारे मुख्य अतिथि खडगे जी के हाथों से बाबा गुरु घासीदास जी के आस्था के प्रतीक और गांव-गांव में निर्मित जैतखाम का शिलान्यास हुआ। सत्य के रास्ते में चलने का संदेश बाबा गुरु घासीदास जी का है। सत्य के रास्ते को महात्मा गांधी जी ने भी बताया। सत्य का रास्ता हमारा रास्ता है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव जी, नरसिम्हा राव जी सभी का उद्देश्य हिंदुस्तान की जनता को ताकतवर बनाने का रहा। हमारा एक ही उद्देश्य रहा है कि कैसे आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सके, महिलाओं के जीवन में कैसे परिवर्तन लाया जा सके।

उन्होंने कहा कि हमारे सुदूर वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी भाइयों बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लघु वनोपज खरीदने की व्यवस्था हमने हर जगह की, धान खरीदी की व्यवस्था हो रही है। देश का तीन चौथाई लघुवनोपज छत्तीसगढ़ में खरीदा जाता है। हमने शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से बीमा योजना शुरू की जिसका लाभ 12.50 लाख संग्राहकों को मिल रहा है। ये छत्तीसगढ़ मॉडल है, जिसमें सबसे किया वायदा हम निभाते हैं। समर्थन मूल्य में धान खरीदी, भूमिहीन मजदूरों को 7 हजार रुपए प्रतिवर्ष आर्थिक अनुदान, अंग्रेजी माध्यम में निःशुल्क शिक्षा देने का वायदा था, हमने दिया। आज छत्तीसगढ़ में किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं, बच्चे सभी को मजबूत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार आपका पैसा आप तक लौटा रही है। हमारी सरकार संसाधनों का उपयोग आपके हित में करती है। आवास बनवाने के लिए हमने 47 हजार परिवार के खातों में 25-25 हजार रुपए की राशि जमा करवा दी। हमने आर्थिक सर्वेक्षण करवाया इसकी रिपोर्ट में जो आया उसके हिसाब से हमने तय किया है कि अब 10 लाख आवासहीन परिवारों को आवास देकर रहेगी।


## कार्यालय अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर मण्डल क्रमांक 1 ( छत्तीसगढ़ )

**निविदा सूचना**

**( द्वितीय आमंत्रण )**

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है:-

| एन.आई.टी. क्र./ सिस्टम टेन्डर नं. | कार्य का विवरण | अनुमानित लागत (लाख में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 173/148632 | STRENGTHENING AND B.T. RENEWAL OF INTERNAL ROAD SCIENCE COLLEGE, RAIPUR | रू. 44.42 लाख |
| 158/148633 | ANNUAL REPAIR WORK FOR BT RENEWAL WORK AT RESIDENTIAL AND NON RESIDENTIAL BUILDINGS RAIPUR C.G. | रू.69.20 लाख |

निविदा डाउनलोड़ करने की अंतिम तिथि दिनांक 18.10.2023 समय सायं 6:30 बजे तक

सभी सक्षम एवं उपयुक्त निविदाकार उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी देखने एवं उपलोड़ करने हेतु ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in पर इंरोल कर निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकते है ।

**अधीक्षण अभियंता**
लो.नि.वि. रायपुर मण्डल क्र.-1
रायपुर ( छ.ग. )

**जी-05925/3**


# बस्तर में एक सुनहरे भविष्य की नई सुबह होने जा रही है: साव

■ अरुण साव ने किया डिजिटल योद्धा कैंपेन का लॉन्च, बने पहले

**रायपुर।** प्रदेश में परिवर्तन यात्रा को मिले रेस्पॉन्स से भूपेश सरकार पूरी तरह घबरा गई है। बौखलाहट में वह अब तमाम लोकतंत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रख कर असभ्यता और आशालीनता पर उतर आई है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ, जब प्रधानमंत्री के आगमन पर राज्य की किसी सरकार ने बंद आयोजित किया हो और प्रधानमंत्री की सभा में जाने से जबरन रोकने की ऐसी साजिश रची हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद अरुण साव ने कहा कि यहां तक कि कांग्रेस की सरकार ऐसी हिम्मत उस पंजाब में भी नहीं कर पाई जहां श्री मोदी जी सुरक्षा से समझौता हुआ था वास्तव में ऐसा कोई राजनीतिक दल कर भी नहीं सकता। खुद कांग्रेस भी अगर महज़ एक राजनीतिक दल होती, तो ऐसी असभ्यता करने के बारे में सोचती भी नहीं।

साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए यह प्रसन्नता की बात थी कि हफ़्ते भर के भीतर प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए थे। बस्तरवासियों, प्रदेशवासियों की दशकों पुरानी आकांक्षाओं को पूरा करने, विकास का सवेरा लाने नगरनार स्टील प्लांट के लोकार्पण समेत 26 हज़ार करोड़ से अधिक के विकास कार्यों को जनता को समर्पित किया। केवल नगरनार प्लांट से ही 50 हज़ार से अधिक छत्तीसगढियों को रोजगार मिलेगा। लेकिन उस शासकीय कार्यक्रम में सीएम तो उपस्थित नहीं हुए और न कैबिनेट का कोई प्रतिनिधि तक उपस्थित नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री की ऐसी ईर्ष्या, ऐसा अमर्यादित आचरण लोकतंत्र में कतई स्वीकार नहीं है। श्री साव ने कहा कि हमें यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि लाख षड्यंत्रों के बावजूद प्रधानमंत्री श्री मोदी की जैसी सफल सभा जगदलपुर के लालबाग मैदान में हुई, आजतक बस्तर ने ऐसी सभा नहीं देखी थी। बस्तर और छत्तीसगढ़ की जनता को जितनी भी बधाई दी जाय, वह कम है। हालाँकि बस्तर बंद और बहिष्कार से कांग्रेस का छत्तीसगढ़ विरोधी, बस्तर विरोधी, विकास विरोधी चेहरा फिर से उजागर हुआ। यह तय हो गया कि भूपेश सरकार को राज्य के विकास से कोई मतलब नहीं है, उसे केवल घोटाले और दस जनपथ की चाटुकारिता करनी है। इसके अलावा न तो उसके पास कोई विजन है, न ही कोई नीयत है विकास की।

साव ने कहा कि बस्तर की जनता ने कांग्रेस को यह बताया कि वह विकास के साथ है। बस्तर अब एक नया सवेरा देखने जा रहा है। अब बस्तर के लोग बाहर रोजगार ढूँढने नहीं जाएंगे, बाहर के लोग रोजगार ढूंढ़ते बस्तर आएंगे। अभी 50 हजार लोगो को नौकरी और आने वाले समय में यह आंकड़ा 1.50 लाख पहुंचेगा। बस्तर के लोगो का जीवन पूरी तरह बदल जायेगा। इसके लिए हम केंद्र की भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं।


## OFFICE OF THE SUPDT. OF POLICE, SUKMA (C.G.)

No./SP/Sukma/AC/ 12 /2023 Dated 29/09/2023

Supdt. of Police Chhattisgarh Distt. Sukma on behalf of Governor Chhattisgarh invites sealed tenders of the following work from approved and eligible contractors for Extension of 11 Kv line from one location to ther other locations as mentioned below as well as establishment of high voltage transformer in the CRPF Kunded. Current Schedule Rate has been adopted as per current status including GST Norms technichally estimatted by the Executive Engineer (O&M) CSPDCL Sukma. The registered Contractors of Category Class III & above shall apply for the given tender. The time of completion including rainy season is 03 months. The office will be received on the office of the SUPDT. OF POLICE, SUKMA up to 15.00 P.M. on Dtd. 15.10.2023 and will be open on dated 15.10.2023 at 17.00 P.M. Tender
form will be issued till date 09.10.2023 up to 17.00 P.M.

| S.No | Name of work | Approximate Cost of Work in lakh | Earnest Money in Rs. |
|---|---|---|---|
| | Erection of 11kv on PCC using Rabbit and 11kv Dp Structure on PCC Pole (140Kg, 8.0 mtr long) and 100KVA SS using H Beam & Single Core Cab and and establishment of high voltage transformer at New CRPF Camp Kunded | 1645936.00 | 12400.00 |

**TENDER NOTE :- Eligibility Criteria**

Tender form will be issued to the bidders only, ofter verification of the correctness of the following

**documents :-**

3. Name address and status of the firm, 2.Vaild registration certificate of CE (ST%RE), CSPDCL, Raipur 3. Experience on execution of External Electrification (mimimum value of work Rs 1.00 Crore) credentials from clients about satisfactory completion of work. 4.Details of works in hence (coy of work order) & present position of work.. 5. Details of works in hance (coy of work order) & present positions of work. 6. Turn over of Rs. 1.00 crore per annum attested by C.A., 7. Coy of latest sail Tax/Commercial Tax pad Certificate. 8. No Relationship Certificate.

**Note:-**

**C.** Cost of tender form of each group will be 750/- in challan of the 0055 Police, 800 Other. B. The contractor interested can bed for single or more groups. C. Successful bidders agreement in form-B applicable for item rate tenders. D. Conditional tender is not acceptable. E. Earnest money un the shope TDR/FDR in fover of SUPDT OF POLICE, SUKMA. F. Location/site can be changed due to additional immediate requirement or security reasons. G. Tender will be accepted the office of SUPDT OF POLICE, SUKMA. F. Within 10 days from the date of issue of contract order, the successful tenderer shall execute an agreement (on stamp paper worth Rs 100) and should start the work as per instruction.

**SUPDT. OF POLICE,**
**DISTT.-SUKMA (C.G.)**

**जी-05924/5**

# फिर उठी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग

**अनिल तिवारी**

विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं और आसन्न लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में भारी संख्या में जुटे सरकारी कर्मचारियों ने एक स्वर से सवाल उठाया कि अर्थशास्त्र का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसमें नेताओं को पेंशन देने से देश प्रगति करता है और कर्मचारियों की पेंशन से देश को घाटा हो जाता है? यह भी कहा गया कि जब देश गरीब था, उस समय भी कर्मचारियों को पेंशन दी जा रही थी। आज जब भारत दुनिया का पांचवा आर्थिक महाशक्ति बन चुका है तो पेंशन क्यों बंद की जा रही है? मालूम हो कि वित्तीय सुधार एवं वित्तीय सुशासन को मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 1999 में ओएएसआईएस की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। कहा गया था कि केंद्र और राज्य सरकारों को अनावश्यक खर्चों में कटौती करने की जरूरत है ताकि खर्च और कमाई के बीच संतुलन बनाकर रखा जा सके। इस रिपोर्ट को आधार बनाकर वित्त वर्ष 2003 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओपीएस की जगह एनपीएस का प्रारूप पेश किया था, जिसे 2004 में एनडीए शासन काल के दौरान लागू किया गया। यूपीए के सत्ता में आने के बाद कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग की, तब कांग्रेसनीत यूपीए सरकार ने इसे खारिज कर दिया। यूपीए सरकार में योजना आयोग के अध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया जैसे अर्थशास्त्री उन दिनों सभी राजनीतिक दलों और राज्यों के सत्ताधारी पार्टियों को सीख दे रहे थे कि वह सभी व्यवस्था को ऐसे कदम उठाने से रोके। अहलूवालिया ने तो ओपीएस को सबसे बड़ी रेवड़ी तक करार दे दिया था। अब जब कांग्रेस विपक्ष में है तो इसे चुनावी मुद्दे के रूप में विभिन्न राज्यों में उछाल रही है और जहां उसे सफलता मिली वहां ओपीएस को बहाल भी कर दिया। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश सहित झारखंड और पंजाब में पुरानी पेंशन योजना लागू है। पूरी संभावना है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल आगामी चुनावी राज्यों और लोकसभा चुनाव में भी पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा जोर-जोर से उठाएंगे। दरअसल भाजपा ने लाभार्थी नामक जो एक पक्का वोट बैंक तैयार किया है, उससे सभी डरे हुए हैं, और उसकी काट के लिए कांग्रेस रास्ता तलाश रही है। यूपीए शासनकाल में पुरानी पेंशन योजना को रेवड़ी बताने वाली कांग्रेस अब सरकारी कर्मचारियों को वोट बैंक के रूप में देख रही है। पुरानी पेंशन योजना के तहत सेवा निवृत कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में उनके अंतिम आहरित वेतन का 50त्न और महंगाई भत्ता दिया जाता है, जबकि नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को हर महीने अपने वेतन का 14त्न अंशदान करना होता है, उसी अनुपात में सरकार भी अंशदान करती है, जो पूंजी बाजार में निवेश होता है। इसी पूंजी निवेश की कमाई सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को पेंशन के रूप में दी जाती है। एनपीएस ट्रस्ट के अनुसार दिसंबर 2022 तक राज्य सरकार के 59.78 लाख कर्मचारी नई पेंशन योजना अपना चुके थे और इसकी कुल परिसंपत्ति 4.7 लाख करोड़ रुपए थी। तत्कालीन सरकार ने वित्त वर्ष 2003 के बजट में एनपीएस लागू करने की घोषणा की थी, बावजूद इसके इसे अपनाना या नहीं अपनाना राज्यों की मर्जी पर छोड़ दिया था।

# जाति आधारित गणना मास्टर स्ट्रोक है ?

**नीरज कुमार दुबे**

बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने जाति आधारित गणना करवा कर उसके आंकड़े जारी कर दिये हैं। बिहार सरकार के इस कदम को बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है। जो लोग नीतीश कुमार सरकार के इस कदम को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं उन्हें समझना होगा कि यह मास्टर स्ट्रोक तब होता जब बिहार को पिछड़ेपन से आजादी मिल जाती, मास्टर स्ट्रोक तब होता जब बिहार में स्कूलों की हालत सुधर जाती, मास्टर स्ट्रोक तब होता जब बिहार में अस्पतालों की हालत सुधर जाती, मास्टर स्ट्रोक तब होता जब बिहार में गुंडाराज और माफिया राज का खात्मा हो जाता, मास्टर स्ट्रोक तब होता जब बिहार में पेपर लीक होना बंद हो जाता, मास्टर स्ट्रोक तब होता जब बिहार में भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता, मास्टर स्ट्रोक तब होता जब बिहार में बेरोजगारी समाप्त हो जाती और पलायन रुक जाता, मास्टर स्ट्रोक तब होता जब बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब पीने से होने वाली मौतें बंद हो जातीं, मास्टर स्ट्रोक तब होता जब बिहार में सड़कों की हालत सुधर जाती। मास्टर स्ट्रोक तब होता जब बिहार में उद्योग-धंधे लग जाते, मास्टर स्ट्रोक तब होता जब बिहार में नौकरी की मांग पर पुलिस लाठीचार्ज होना बंद हो जाता। मास्टर स्ट्रोक तब होता जब बिहार भी जीएसटी संग्रहण में कुछ योगदान कर पाता। इसलिए नीतीश कुमार का यह फैसला मास्टर स्ट्रोक नहीं बिहार को पीछे धकेलने का प्रयास है।

यह बात सही है कि सरकार के पास जनसंख्या संबंधी विस्तृत आंकड़े होंगे तो विकास योजनाएं बनाने में आसानी होगी लेकिन जब जाति जनगणना के आंकड़े जल्द ही होने वाली राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना से भी हासिल किये जा सकते हैं तो राज्यों को अपनी मशीनरी का इस्तेमाल जाति आधारित राजनीति के लिए करने से बचना चाहिए। हम आपको बता दें कि बिहार मंत्रिमंडल ने पिछले साल दो जून को जाति आधारित गणना कराने की मंजूरी देने के साथ इसके लिए 500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की थी। जरा सोचिये, यदि यह राशि विकास कार्यों में लगाई गयी होती तो राज्य के लोगों को इसका कितना लाभ मिलता। जरूरत इस बात की थी कि नीतीश कुमार अपने लंबे कार्यकाल में किये गये कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जारी कर अपनी उपलब्धियां बताते लेकिन उन्होंने जाति आधारित गणना करवा कर चर्चा को दूसरी ओर मोड़ने का प्रयास किया है।

बिहार सरकार में शामिल नेता अब हुँकार भर रहे हैं कि वह राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना के लिए माहौल बनाएंगे। कुछ लोग इसे मंडल पार्ट-2 कह रहे हैं। ऐसे नेताओं को याद रखना चाहिए कि मंडल भाग-1 के दौरान कुछ लोगों द्वारा जिस तरह की राजनीति की गयी थी उससे समाज को बहुत नुकसान हुआ था और देश में अशांति फैली थी इसलिए बिहार सरकार ने जो कुछ किया उसे मंडल पार्ट-2 की संज्ञा देकर माहौल को बिगाड़ा नहीं जाना चाहिए। आज जब देश तरक्की के रास्ते पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। दुनिया भर में मंदी के माहौल के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है और हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर कदम बढ़ा चुके हैं, ऐसे में विकास की बात ना कर जाति को महत्व देना गलत है। जरा दुनियाभर में नजर उठा कर देखिये किस विकसित देश ने आगे बढ़ने के लिए जाति या धर्म को महत्व दिया है?

हम आपको यह भी याद दिला दें कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्य में जाति आधारित गणना का आदेश पिछले साल तब दिया था, जब केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह आम जनगणना के हिस्से के रूप में एससी और एसटी के अलावा अन्य जातियों की गिनती नहीं कर पाएगी। देखा जाये तो मोदी सरकार का यह कहना पूर्णतया तर्कसंगत था कि जनगणना करते समय अन्य पिछड़ी जातियों की गणना नहीं की जाएगी। जहां तक पिछड़ों की गणना का सवाल है, पहली बात तो यह है कि अक्सर हर जाति के लोग अपने आप को पिछड़ा बताने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। उसका नतीजा यह होता है कि किसी प्रदेश के एक जिले में जो जाति सवर्ण है, वही दूसरे प्रदेश के अन्य जिले में पिछड़ी है।

हम आपको यह भी बता दें कि देश में आखिरी बार सभी जातियों की गणना 1931 में की गई थी। 1931 की जनगणना में जातियों की संख्या पूरे भारत में 4147 थी लेकिन 2011 की जनगणना में उनकी संख्या छलांग मारकर 46 लाख तक पहुंच गई। देखा जाये तो किसी भी व्यक्ति की जाति को निर्धारित करने का कोई निश्चित वैज्ञानिक पैमाना नहीं है। वह जो कह दे, वही सही है। सच्चाई तो यह है कि पिछड़ा, पिछड़ा होता है। उसकी कोई जाति नहीं होती। हर जाति में पिछड़े हैं और हर जाति में अगड़े हैं। इसीलिए जनगणना करने वाले बाबू लोग कभी-कभी बड़े विभ्रम में पड़ जाते हैं। वे देखते हैं कि गांवों के बड़े-बड़े जमींदार, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, वह अपनी जाति के आधार पर अपने को पिछड़ों में शामिल करवा लेते हैं। हम आपको यह भी याद दिला दें कि सरकार ने 2011 में पिछड़ेपन का सर्वेक्षण करवाया था। उसमें जाति संबंधी जानकारी भी मांगी गयी थी लेकिन 2010-11 में चले 'मेरी जाति हिंदुस्तानी' आंदोलन ने इतना तगड़ा दबाव बनाया कि सरकार ने उन आंकड़ों को जारी ही नहीं किया था।

बहरहाल, मोदी सरकार का यह संकल्प स्वागत योग्य है कि वह जातीय जनगणना नहीं करवाएगी। वैसे भी जाति जनगणना पिछड़ों के भले के लिए नहीं नेताओं ने अपने भले के लिए कराई है ताकि हिंदू समाज को बांट कर अपने राजनीतिक हितों को साधा जाये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इस मुद्दे पर विपक्ष पर हमला यह कहते हुए बोल ही दिया है कि कांग्रेस ने गरीबों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है और छह दशकों तक देश को जाति के आधार पर विभाजित किया है और यह पाप वह अब भी कर रही है। जो लोग इस बात की गलतफहमी पाले बैठे हैं कि जाति आधारित गणना के चलते अगले लोकसभा चुनावों के लिए माहौल पूरी तरह भाजपा के खिलाफ हो जायेगा, उन्हें यह समझना होगा कि देश का कोई एक भाग भले जाति आधारित राजनीति के कुचक्र से अब तक बाहर नहीं निकला हो लेकिन बाकी देश विकास की मुख्यधारा से जुड़कर आगे बढ़ रहा है और चुनाव में मतदान देशहित से जुड़े मुद्दों को देखते हुए ही करेगा।

**भारतीय ज्ञान परंपरा....**

# महोपनिषद् (भाग-7)

**गतांक से आगे...**

अपने पिता (ऋभु) से अनुमति लेकर निदाघ नामक श्रेष्ठ मुनिपुत्र एकाकी ही तीर्थयात्रा के लिए चल पड़े। साढ़े तीन करोड़ तीर्थ स्थलों में स्नान आदि सम्पन्न कर लेने के पश्चात् वे श्रेष्ठ मुनि अपने घर वापस लौट आए। उन महान् यशस्वी मुनि ने घर आकर अपने पिता ऋभुमुनि से अपनी समस्त यात्रा का वृत्तान्त कह सुनाया। उन्होंने कहा- हे पिताजी! साढ़े तीन करोड़ तीर्थस्थलों में स्नान करने के पश्चात् जो पुण्य फल प्राप्त हुआ है, उसके प्रतिफल स्वरूप हमारे अन्त:करण में इस तरह के श्रेष्ठ विचार प्रादुर्भूत हो रहे हैं।

यह जगत् उत्पन्न होता है मरने (विनष्ट होने) के लिए, पुन: मरता है जन्मने के लिए। समस्त चराचर प्राणियों की चेष्टा के साथ यह सारा प्रपञ्च (जगत) अस्थिर एवं क्षणिक है। ऐश्वर्य की भूमि में प्रकट होने वाले ये समस्त पदार्थ आपत्तियों के मूलभूत कारण हैं। ये सभी पदार्थ लौह शलाका के सदृश परस्पर पृथक् रहते हुए मानसिक कल्पना रूपी चुम्बक द्वारा एकत्रित होते रहते हैं। जिस तरह मार्ग में गमन करने वाला व्यक्ति मरुस्थल में चलते-चलते (कष्ट के कारण) विरक्त हो जाता है, उसी तरह मैं भी इन सांसारिक पदार्थों से विरक्त हो रहा हूँ; क्योंकि ये सांसारिक भोग पदार्थ मुझे दु:खदायी प्रतीत होने लगे हैं।

अब इन समस्त दु:खों का शमन किस प्रकार होगा, ऐसा सोचकर मेरा हृदय अत्यधिक संतप्त हो रहा है। ये ऐश्वर्य रूपी धन-जिनके पीछे चिन्ताओं के समूह चक्र की भाँति घूमते रहते हैं, मुझे आनन्दप्रद नहीं लग रहे हैं। स्त्री पुत्रादि समस्त स्वजन सम्बन्धी मानो उग्र आपदाओं के घर हैं। हे मुनीश्वर! इस जगत् में उदारता की प्रतिमूर्ति, अत्यन्त कोमलांगी ये श्रीलक्ष्मी जी भी परम मोह को उत्पन्न करने वाली हैं। निश्चय ही इनके द्वारा जीव को आनन्द नहीं मिल सकता। जिस प्रकार पल्लव के अग्रभाग में जल कणिका बूंदरूप में लटकती हैं, वह क्षणिक है। उसी प्रकार मनुष्य की आयु भी जल की बूँद के सदृश क्षणभंगुर है। इस नाशवान् शरीर को असमय ही छोड़कर उन्मत्त की भाँति मुझे प्रस्थान करना ही पड़ेगा। जिनका चित्त विषय-वासना रूपी सर्प के सङ्ग से जर्जर हो गया है तथा जिन्हें प्रौढ़ आत्मिक ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, उनका जीवन कष्ट का ही हेतु बना है।

वायु का लपेटना, आकाश को खण्ड-खण्ड करना एवं जल की लहरों का गुन्धन भले ही सम्भव हो जाए, किन्तु जीवन में आस्था एवं विश्वास रखना सम्भव नहीं हो पाता। जिसके द्वारा प्राप्त करने योग्य वस्तु को (सम्यक् रूप से) प्राप्त कर लिया जाता है, जिसके कारण शोक न करना पड़े और जिसमें परम शान्ति की उपलब्धि हो जाए, वही तो वास्तविक जीवन कहलाता है। यों तो वृक्ष, मृग एवं पक्षी भी जीवन धारण किये रहते हैं; किन्तु यथार्थ में वही जीवित है, जिसका मन निरन्तर आत्मचिन्तन में लीन रहता है।

**क्रमश: ...**

# राष्ट्र के प्रकाश स्तम्भ होते हैं शिक्षक

**रमेश सर्राफ धमोरा**

देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ राधाकृष्णन का जन्म पांच सितम्बर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही किताबें पढ़ने के शौकीन थे और स्वामी विवेकानंद से काफी प्रभावित थे। डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षक थे। जिन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष अध्यापन पेशे को दिया है। वो विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षकों के योगदान और भूमिका के लिये प्रसिद्ध थे। इसलिये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षकों के बारे में सोचा और हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रुप में मनाने का अनुरोध किया।

शिक्षक हर व्यक्ति के जीवन की रीढ़ होते हैं। शिक्षक ही है जो छात्रों को जीवन का नया अर्थ सिखाता है। वे हमें सही रास्ता दिखाते हैं और कुछ भी गलत करने से रोकते हैं। वे बाहर से देख सकते हैं। वे प्रत्येक छात्र की देखभाल करते हैं और उनके विकास की कामना करते हैं। उस छात्र को मत भूलो जो छात्र अपने शिक्षकों का सम्मान नहीं करता है। वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ता है। शिक्षक छात्र के व्यक्तित्व को ढालते हैं। वे एकमात्र नि:स्वार्थ व्यक्ति हैं जो खुशी-खुशी बच्चों को अपना सारा ज्ञान देते हैं। शिक्षक विद्यार्थियो के जीवन के वास्तविक निर्माता होते हैं जो न सिर्फ हमारे जीवन को आकार देते हैं। बल्कि हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम पूरी दुनिया में अंधकार होने के बाद भी प्रकाश की तरह जलते रहें। शिक्षक समाज में प्रकाश स्तम्भ की तरह होता है। जो अपने शिष्यों को सही राह दिखाकर अंधेरे से प्रकाश की और ले जाता है। शिक्षकों के ज्ञान से फैलने वाली रोशनी दूर से ही नजर आने लगती है। इस वजह से हमारा राष्ट्र ढ़ेर सारे प्रकाश स्तम्भों से रोशन हो रहा है। इसलिये देश में शिक्षकों को सम्मान दिया जाता है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच के रिश्तों को सुदृढ़ करने को शिक्षक दिवस एक बड़ा अवसर होता है।

कहा जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा रहता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। हमारे जीवन में सबसे पहली गुरु तो मां होती है जो हमें जन्म लेते ही हर बातों का ज्ञान कराती है। मगर विद्यार्थी काल में बालक के जीवन में शिक्षक एक ऐसा गुरु होता है जो उसे शिक्षित तो करता ही है साथ ही उसे अच्छे बुरे का ज्ञान भी कराता है। पहले के समय में तो छात्र गुरुकुल में शिक्षक के पास रहकर वर्षों विद्या अध्ययन करते थे। उस दौरान गुरु अपने शिष्यों को विद्या अध्ययन करवाने के साथ ही स्वावलंबी बनने का पाठ भी पढ़ाते थे। इसीलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का स्थान ईश्वर से भी बड़ा माना गया है, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही व्यक्ति ईश्वर को भी प्राप्त करता है। हमारे जीवन को संवारने में शिक्षक एक बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। सफलता प्राप्ति के लिये वो हमें कई प्रकार से मदद करते है। जैसे हमारे ज्ञान, कौशल के स्तर, विश्वास आदि को बढ़ाते है तथा हमारे जीवन को सही आकार में ढ़ालते है। कबीर दास ने शिक्षक के कार्य को इन पंक्तियो में समझाया है:-

गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ि गढ़ि काढ़ै खोट,
अंतर हाथ सहार दै, बाहर बाहै चोट।

कबीर दास जी कहते है कि शिक्षक एक कुम्हार की तरह है और छात्र पानी के घड़े की तरह। जो उनके द्वारा बनाया जाता है और इसके निर्माण के दौरान वह बाहर से घड़े पर चोट करता है। इसके साथ ही सहारा देने के लिए अपना एक हाथ अंदर भी रखता है। पुराने समय में शिक्षकों को चरण स्पर्श कर सम्मान दिया जाता था। परन्तु आज के समय में शिक्षक और छात्र दोनो ही बदल गये है। पहले शिक्षण एक पेशा ना होकर एक उत्साह और एक शौक का कार्य था। पर अब यह मात्र एक आजीविका चलाने का साधन बनकर रह गया है।

# चेहरा नहीं बनीं, तो चेहरा बिगाड़ भी सकती है वसुंधरा

**निरंजन परिहार**

राजस्थान में बीजेपी के नेता भले ही यह कहते घूम रहे हों कि चुनाव किसी चेहरे पर नहीं बल्कि कमल के निशान पर ही होगा, लेकिन चुनाव माथे पर आते आते उनको भी यह साफ लगने लगा है कि सत्ता में आना वसुंधरा राजे के बिना आसान नहीं है। भले ही मध्य प्रदेश में वसुंधरा राजे की छोटी बहन यशोधरा राजे से बीमारी के बहाने चुनाव न लड़ने और महल में विराजने की घोषणा करवा दी गई हो, या फिर गुजरात में टिकट काटकर घर बिठा दिए गए ताकतवर नेता नितिन पटेल को राजस्थान में उप प्रभारी जैसे मामूली पद पर बिठाकर ये साफ संकेत दे दिए गए हों कि केंद्र के सामने किसी की मनमर्जी नहीं चलती। लेकिन राजस्थान न तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गुजरात है और न ही मध्य प्रदेश, जहां पर मोदी के कहने पर विधानसभा में सीधे सीधे वोट पड़ जाएं और बीजेपी आसानी से सत्ता में आ सके। दरअसल, अशोक गहलोत ने अपने रणनीतिक कौशल के जरिए राजनीति में खुद को इतना बड़ा बना लिया है कि पार्टी के भीतर ही कांग्रेस आलाकमान भी अब उनके लिए कोई चैलेंज नहीं है। धड़ाधड़ शुरू की गई धमाकेदार जनलाभकारी योजनाओं के जरिए जनता को अपने साथ जोड़कर खुद के लिए एक ऐसा राजनीतिक कवच निर्मित कर लिया है, जिसके कारण बीजेपी की सत्ता आना उतना आसान नहीं है जितना बीजेपी के नेता कह रहे हैं।

राजनीति के इसी मुश्किल मोड़ पर वसुंधरा राजे बीजेपी की राजनीतिक मजबूरी बन रही है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के चाणक्य कहे जानेवाले ताकतवर गृहमंत्री अमित शाह तक कोई तरकीब तलाशने में व्यस्त हैं कि है कि आखिर वसुंधरा राजे के बिना गहलोत को गुड़काकर राजस्थान में बीजेपी को सत्ता में कैसे लाया जाए? पहले थोड़ा इतिहास में झांकते हैं। राजस्थान में वर्ष 1993 में बीजेपी के भैरोंसिंह शेखावत लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। मगर उनको हराकर वर्ष 1998 में कांग्रेस से जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद से लगातार हर पांच साल बाद एक बार कांग्रेस, और एक बार बीजेपी की सरकारें बनने का सिलसिला चल गया। इन पांच चुनावों में तीन बार कांग्रेस से अशोक गहलोत तो दो बार बीजेपी से वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही हैं। हर पांच साल बाद सत्ता के बदलने की कहानी जारी रही है। जनता ने भी इसे एक ट्रेंड के रूप में अपने भीतर उतार लिया है कि जो सरकार है, उसे लगभग बदलना ही है।

इसी वजह से 2013 के चुनाव में जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंनें लोगों के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं लागू की थीं, लेकिन कांग्रेस 200 में से केवल 22 सीटें ही जीत सकी। इसी वजह से इस बार अशोक गहलोत भले ही जबरदस्त योजनाएं लेकर जनता के बीच हैं और लगभग उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चुनाव जीतने की तर्ज पर जनलाभकारी योजनाओं के लाभार्थियों से जुड़कर जीत की जुगत लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी गहलोत की हर काट का सामान जुटा रही है।

हां, वसुंधरा राजे का फैक्टर बीजेपी के लिए एक ऐसा फच्चर बन गया है, जिसका तोड़ वह चाहकर भी निकाल नहीं पा रही है। बीजेपी आलाकमान इस संभावना पर आश्रित है कि इस बार चुनाव बेहद रोचक हो गया है। हो सकता है कि अंत में नतीजा तीन दशक से होते रहे बदलाव का रिवाज का साथ निभाता नजर आए लेकिन बीजेपी में वसुंधरा राजे ने इस पूरे चुनाव को चर्चा में ला दिया है। आलम यह है कि राजस्थान को लेकर, खासकर वसुंधरा राजे को लेकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी बीजेपी सतर्क है, सावधान है। राजस्थान में सही मायने में वसुंधरा राजे बेहद कद्दावर नेता है। इस बात में किसी को कोई शक नजर नहीं आता। फिर मोदी, शाह और नड्डा की राजे को दरकिनार करने की कोशिशों ने इस तथ्य को स्थापित भी कर दिया है। इसीलिए देखा जाए तो साफ लगता है कि वसुंधरा के राजनीतिक वर्तमान और भविष्य के बीच यह चुनाव झूल रहा है और उसी पर पहुंचकर लगभग अटक सा गया है।

राजस्थान में अपने दम पर बीजेपी को बहुमत दिलाने वाली दो बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करवाने की कोशिश में कई साधना, आराधना और जप - तप भी किए हैं। लेकिन बीजेपी आलाकमान चुनाव सिर पर होने के बावजूद यह आकलन करने में लगा है कि क्या वसुंधरा के बिना चुनाव जीता जा सकता है या नहीं। राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 73 विधायक जीते थे। इसमें से लगभग आधे वसुंधरा समर्थक हैं, जो वर्तमान में विधानसभा में बैठे हैं और फिर से उम्मीदवारी भी चाह रहे हैं। बीजेपी का चतुर आलाकमान यह दिखा तो नहीं रहा है, लेकिन उसे डर जरूर सता रहा है कि अगर वसुंधरा को हाशिये पर लाया गया तो गहलोत के मुकाबले कहीं बीजेपी सत्ता की दौड़ में बैठ न जाए। क्योंकि अशोक गहलोत भी इस बार इतिहास बदलने की कोशिश में चुनावी मुद्रा में मैदान में खड़े हैं और प्रदेश की जनता में अपनी इस बार की योजनाओं व अपने लाभ देनेवाले जनकार्यों के जरिए फिर से आने की धारणा को प्रबल कर चुके हैं। बीजेपी आलाकमान का एक डर यह भी है कि वसुंधरा को दरकिनार करने और गहलोत के बढ़ते कद के कारण त्रिशंकु विधानसभा की सूरत में वसुंधरा राजे कांग्रेस के समर्थन में कोई ऐसा ही खेल न कर दे, जैसा मध्य प्रदेश में उनके भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के लिए किया था।

राजस्थान में अपनी ही पार्टी में दरकिनार किए जाने की कोशिशों के बीच वसुंधरा राजे जहां भी जाती हैं, जनता उनको घेर लेती हैं। अपने दौरों में वे अपनी ओर से खुद को लगभग मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करते हुए जनता को अपनी शक्ति बताती हैं। वे लोगों से कहती है कि आपकी इस अटूट शक्ति की वजह से मैं राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी। आपकी सेवा करूंगी, आपके साथ रहूंगी। आपकी आवाज आपके साथ उठाने में कोई कमी नहीं रखूंगी। आपकी शक्ति, आपका साथ, आशीर्वाद बना हुआ है। आपका ये साथ इतना मजबूत है कि जो कोई भी तोड़ने की कोशिश करेगा, टूटेगा नहीं। लेकिन इसके बाद भी जनसभाओं में नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा वसुंधरा को कोई बहुत भाव नहीं देने और महिला आरक्षण विधेयक पारित करवाने के तत्काल बाद ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कमल को ही राजस्थान में चुनावी चेहरा घोषित कर देना साफ तौर से वसुंधरा की अहमियत को कमजोर करने की कोशिश माना जा रहा है। हालांकि राजस्थान की महिलाओं में लोकप्रियता के शिखर पर विराजमान वसुंधरा इसके बावजूद मोदी के महिला आरक्षण बिल की प्रशंसा में महिलाओं के बीच यह कहती है कि मोदी जी ने सही किया है क्योंकि मातृ शक्ति की भागीदारी के बिना किसी भी राष्ट्र के नव निर्माण की कल्पना अधूरी है। वे महिलाओं का जोश देख कर यह भी कहती है कि नारी शक्ति का यह प्रवाह राजस्थान की महिला विरोधी कांग्रेस सरकार को बहा कर ले जाएगा। लेकिन असल मुद्दा चेहरे का है। चेहरा नहीं बनीं, तो क्या चेहरा बिगाड़ कर रख देगी वसुंधरा? बीजेपी आलाकमान इसी कोशिश में है कि वसुंधरा की वजह से बात और चेहरा दोनों ही न बिगड़े और सरकार भी बन जाए। लेकिन राजनीति में हर कोशिश कामयाब ही होती है, ऐसा अक्सर नहीं होता।

**हिन्द स्वराज्य**

# गोला-बारूद (भाग-4)

**गतांक से आगे...**

आपका धर्म किसी भी साधन से चोर को घर से निकालने का हरगिज नहीं है। जरा आगे बढ़े। वह हथियारबंद आदमी आपकी चीज ले गया है। आपने उसे याद रखा है। आपके मन में उस पर गुस्सा भरा है। आप उस लुच्चे को अपने लिए नहीं, लेकिन लोगों के कल्याण के लिए सजा देना चाहते हैं। आपने कुछ आदमी जमा किये। उसके घर पर आपने धावा बोलने का निश्चय किया। उसे मालूम हुआ। वह भागा। उसने दूसरे लुटेरे जमा किये। वह भी खीजा हुआ है। अब तो उसने आपका घर दिन-दहाड़े लूटने का संदेशा आपको भेजा है। आप उसके मुकाबले के लिए तैयार बैठे हैं। इस बीच लुटेरा आपके आसपास के लोगों को हैरान करता है। वे आपसे शिकायत करते हैं। आप कहते हैं यह सब मैं आप ही के लिए तो करता हूँ। मेरा माल गया उसकी तो कोई बिसात ही नहीं। लोग कहते हैं पहले तो वह हमें लूटता नहीं था। आपने जबसे उसके साथ लड़ाई शुरू की है तभी से उसने यह काम शुरू किया है। आप दुविधा में फँस जाते हैं। गरीबों के ऊपर आपको रहम है। उनकी बात सही है। अब क्या किया जाय? क्या लुटेरे को छोड़ दिया जाय? इससे तो आपकी इज्जत चली जायेगी। इज्जत सबको प्यारी होती है। आप गरीबों से कहते है कोई फिक्र नहीं। आइये, मेरा धन आपका ही है मैं आपको हथियार देता हूँ। मैं आपको उनका उपयोग सिखाऊँगा। आप उस बदमाश को मारिये, छोड़िये नहीं। यों लड़ाई बढ़ी। लुटेरे बढ़े। लोगों ने खुद होकर मुसीबत मोल ली। चोर से बदला लेने का परिणाम यह आया कि नींद बेचकर जागरण मोल लिया। जहाँ शान्ति थी वहाँ अशान्ति पैदा हुई। पहले तो जब मौत आती तभी मरते थे। अब तो सदा ही मरने के दिन आये। लोग हिम्मत हारकर पस्त हिम्मत बने। इसमें मैंने बढ़ा-चढ़ाकर कुछ नहीं कहा है, यह आप धीरज से सोचेंगे तो देख सकेंगे। यह एक साधन हुआ। अब दूसरे साधन की जाँच करें। चोर को आप अज्ञान मान लेते हैं। कभी मौका मिलने पर उसे समझाने का आपने सोचा है। आप यह भी सोचते हैं कि वह भी हमारे जैसा आदमी है। उसने किस इरादे से चोरी की, यह आपको क्या मालूम? आपके लिए अच्छा रास्ता तो यही है कि जब मौका मिले तब आप उस आदमी के भीतर से चोरी का बीज ही निकाल दें। ऐसा आप सोच रहे हैं, इतने में वे भाई साहब फिर से चोरी करने आते हैं। आप नाराज नहीं होते। आपको उस पर दया आती है। आप सोचते हैं कि यह आदमी रोगी है।

**क्रमश: ...**

# जातिगत सर्वे के सामाजिक-आर्थिक पहलू

**प्रो. अरुण कुमार**

बिहार में जातिगत सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए गए हैं और इन आंकड़ों के सामने आते ही पूरे देश में इसको लेकर सियासत गरमा गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में जातिगत सर्वे कराने की मांग की जा रही है और कर्नाटक में 2015 में हुए जातिगत सर्वे के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग उठने लगी है।

बिहार में हुए सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में सबसे बड़ी आबादी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है, जो कुल आबादी के करीब 36 फीसदी है। इससे बिहार की स्थिति का तो पता चल रहा है, लेकिन पूरे देश में क्या स्थिति है, वह भी पता चलना चाहिए। लिहाजा, अब केंद्र सरकार पर यह दबाव बढ़ जाएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े तैयार करके सार्वजनिक करे, ताकि कुल आबादी में जातिगत अनुपात का पता चल सके, जिससे उनके रोजगार एवं शिक्षा में बेहतर हिस्सेदारी के लिए आवश्यक नीतियां बनाई जा सकें।

बिहार की कुल आबादी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का अनुपात बढ़ गया है, जो स्वाभाविक लगता है। इसकी वजह यह है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में गरीबी ज्यादा है। जो गरीब होते हैं, वे शिक्षा व जागरूकता की कमी तथा बुढ़ापे में अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। गरीबों के पास बचत तो होती नहीं, ऐसे में बच्चे ही उनके लिए सामाजिक सुरक्षा का आधार होते हैं। वे यह सोचते हैं कि ज्यादा बच्चे होंगे, तो ज्यादा कमाकर लाएंगे और बुढ़ापे में उनका ख्याल रखेंगे। लेकिन जैसे-जैसे लोगों की समृद्धि बढ़ती है, परिवार में खुशहाली बढ़ती है, वैसे-वैसे लोग कम बच्चे पैदा करते हैं। मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होती है, इसलिए वे लोग कम बच्चे पैदा करते हैं, जिससे उनकी

जनसंख्या धीमी गति से बढ़ती है।

अब सवाल उठता है कि हमें करना क्या है। ऊपरी जाति के लोग इस बात से चिंतित हैं कि चूंकि अत्यंत पिछड़ी जातियों का आबादी में ज्यादा अनुपात है, इसलिए उनकी आरक्षण की मांग बढ़ जाएगी। मेरा मानना है कि अगर हम शुरू से ही अत्यंत पिछड़ी जातियों को रोजगार और शिक्षा में ज्यादा तवज्जो देते, तो आज जो यह स्थिति आई है, वह नहीं आई होती। अगर रोजगार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों, तो आरक्षण से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आरक्षण से तब फर्क पड़ता है, जब रोजगार का संकट होता है।

रोजगार के संकट की स्थिति में ही आरक्षण को लेकर झगड़ा पैदा होता है कि किसको कितना रोजगार मिल रहा है। इस समय चूंकि रोजगार का भारी संकट है, बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, सरकारी नौकरियां कम हैं, ऐसे में आरक्षण की मांग बढ़ रही है। समस्या इसलिए बढ़ी है कि आजादी के बाद हमने टॉप-डाउन एवं ट्रिकल-डाउन की नीति अपनाई। इसका नतीजा यह हुआ कि समाज के ऊपरी तबके को तो सभी फायदे मिले, लेकिन निचले तबके को लाभ नहीं मिला या मिला भी, तो बहुत कम। इसलिए झगड़ा बढ़ गया।

नई प्रौद्योगिकी ने भी बेरोजगारी बढ़ाने में योगदान दिया है। हमारे देश में रोजगार सृजन में कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा है, लेकिन ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, थ्रेसर, आलू खोदने की मशीन इत्यादि का इस्तेमाल बढ़ने से रोजगार पैदा नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा, हमारी सरकारें भी अभी ऐसी नीतियां अपना रही हैं, जिनमें संगठित क्षेत्र को तो बढ़ावा मिलता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र (जहां ज्यादातर लोग काम करते हैं) पिछड़ता चला जा रहा है।

उदाहरण के लिए, सरकार ने कॉरपोरेट सेक्टर को कर छूट दी, पीएलए स्कीम चलाई, जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आवंटन में कटौती कर दी। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के आवंटन में भी कटौती कर दी गई है, जबकि इन दोनों क्षेत्रों में ज्यादा रोजगार पैदा होता है। ज्यादातर निवेश बड़ी-बड़ी परियोजनाओं में किया जा रहा है, जहां आधुनिक प्रौद्योगिकी के जरिये मानव श्रम को विस्थापित किया जा रहा है। इन वजहों से समाज में असमानता की खाई और चौड़ी होती चली गई और यह झगड़ा ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसलिए जो नीचे का तबका और उन तबकों के लिए सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाली पार्टियां मांग करने लगी हैं कि अत्यंत पिछड़ी जातियों को आबादी में उसके अनुपात के हिसाब से आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।

बिहार के जातिगत सर्वे के सार्वजनिक होने से अन्य राज्यों में भी ऐसे सर्वे कराए जाने की मांग तो उठने ही लगी है, अब यह भी मांग उठेगी कि आरक्षण की अधिकतम सीमा, जो 50 फीसदी निर्धारित है, उसे बढ़ाया जाए। लेकिन असली मुद्दा रोजगार संकट का है, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलने का है। जब सामाजिक रूप से सही नीतियों को समय पर लागू नहीं किया जाता है, तो सामाजिक संघर्ष होता है और अलगाव फैलता है। हम उन नीतियों को लागू करने के लिए मजबूर हैं, जो राष्ट्र के लिए अनुकूल नहीं हैं।

जातिगत सर्वे के विरोधी यह तर्क देते हैं कि इस तरह के सर्वे के आंकड़ों में जिन जातियों की संख्या कम होगी, वे परिवार नियोजन की नीतियों को दरकिनार कर अपनी आबादी बढ़ाने की होड़ में लग जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। दुनिया भर में जैसे-जैसे परिवार में समृद्धि बढ़ती है, शिक्षा का स्तर बढ़ता है, लोग परिवार नियोजन को अपनाते हैं और कम बच्चे पैदा करते हैं। कम आबादी वाले समृद्ध परिवारों के लोग अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए उन्हें शिक्षा एवं रोजगार के लिए विदेश में भेजने लगेंगे और यह अब भी हो रहा है।

बिहार के जातिगत सर्वे के आंकड़ों के राजनीतिक निहितार्थ तो स्पष्ट हैं ही और इसका राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर पड़ना लाजिमी है। सभी राजनीतिक पार्टियां इसका अपने-अपने ढंग से इस्तेमाल करना चाहेंगी और देश में एक बार फिर से मंडल-कमंडल की राजनीति और बढ़ जाएगी। लेकिन भाजपा के लिए स्थिति थोड़ी भिन्न है, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में भाजपा को पिछड़ी जातियों का काफी वोट मिला है। आने वाले चुनाव में राजनीतिक पार्टियां आरक्षण के मुद्दे को जोर-शोर से उठा सकती हैं। आरक्षण की अधिकतम निर्धारित सीमा को बढ़ाने की भी मांग उठ सकती है। सत्ता पक्ष बेशक इसे बढ़ाना नहीं चाहेगा, लेकिन संभावित चुनावी नुकसान को देखते हुए वह भी मुखर विरोध नहीं करेगा, बल्कि सनातन, आतंकवाद, चीन-पाकिस्तान जैसे अन्य मुद्दों की तरफ बहस को मोड़ना चाहेगा।

# बिहार के जाति गणना से बदलेगी राजनीति

**संजय कुमार**

विपक्षी दल लगभग एक साल से देश में जाति-गणना की मांग कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर बैकफुट पर थी। उसके पास इसे लेकर टालमटोल करने के बारे में कोई खास जवाब नहीं था। भाजपा ने कुछ महीनों से एक तर्क खोज लिया था कि कुछ राज्यों में ऐसी गणना तो हुई, मगर आंकड़े जारी नहीं किये गये। वे कर्नाटक का उदाहरण देकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश करते थे। ऐसे ही बिहार को भी घेरने की कोशिश करते थे और विपक्ष भी बचता दिखता था। लेकिन अब बिहार जाति सर्वेक्षण करने और उसकी रिपोर्ट जारी करनेवाला देश का पहला राज्य बन गया है। इससे बीजेपी के हाथ से विपक्ष को घेरने का एक हथियार निकल गया है। राजनीतिक नजरिये से देखें तो अभी बीजेपी-एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच शह और मात का खेल चल रहा है। महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के समय लग रहा था कि भाजपा चार कदम आगे निकल गयी है और उसने ऐसा काम कर डाला जिसका कोई विरोध नहीं कर सका। विपक्ष के हाथ में बस महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण की मांग का मुद्दा रह गया था, फिर भी उन्होंने बिल को समर्थन दिया। लेकिन बिहार में जातियों के आंकड़े आने के बाद क्रिकेट की भाषा में भाजपा थोड़ा-सा बैकफुट पर चली गयी है। विपक्ष ने पिच तैयार कर दी है, और वे फ्रंटफुट पर बैटिंग करने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। अब ये खेल चुनाव होने तक चलता रहेगा। ऐसा लगने लगा है कि 2024 के आम चुनाव में सामाजिक न्याय का मुद्दा जोर पकड़ेगा। पहले ऐसा लग रहा था कि विपक्षी पार्टियां जाति गणना को लेकर केवल शोर करती रहेंगी और चुनाव में यह मुद्दा प्रभावी नहीं होगा। लेकिन, इस मुद्दे की गर्माहट का थोड़ा अंदाजा तब मिला जब विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण में भी ओबीसी आरक्षण की मांग की, और बीजेपी को इस बारे में सफाई देनी पड़ी। तब बीजेपी के तमाम मंत्रियों ने इन आंकड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया कि उनकी पार्टी से 85 ओबीसी सांसद हैं, और 29 ओबीसी मंत्री हैं, और इतने ओबीसी विधायक हैं। भाजपा को यह लगने लगा था कि जनता विपक्ष के हमले को कहीं गंभीरता से ना ले ले, और इसलिए उसने प्रमाण देना शुरू कर यह जताने की कोशिश की कि विपक्ष भले ही ओबीसी समुदाय का हिमायती बनता हो, लेकिन उन्हें असल प्रतिनिधित्व तो भाजपा ने दिया है। उन्होंने तब ये भी कहा कि उनके तो प्रधानमंत्री भी ओबीसी हैं। उस समय ऐसा लगने लगा कि यह 2024 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद अब इस बारे में कोई शक नहीं रह गया है कि आनेवाले चुनाव में दोनों खेमों की ओर से सामाजिक न्याय के इर्द गिर्द गोलबंदी के प्रयास किये जाएंगे। एक सवाल यह भी जरूर उठ रहा है कि क्या अगले चुनाव में फिर एक बार मंडल और कमंडल के मुद्दों की वापसी हो सकती है। इसका पता तो चुनाव के नतीजों के बाद चलेगा लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी आहट जरूर सुनाई पड़ी है। बल्कि यह कहना सही होगा कि आहट तो पहले से सुनाई देने लगी थी, अब वह दरवाजे पर दस्तक देने लगी है। अगले चुनाव में मंडल 2.0 की संभावना पूरी तरह से दिखाई दे रही है। मैच अब थोड़ा और खुल गया है। एक साल पहले तक ऐसा लगता था कि एक तरफ एक बहुत मजबूत टीम है, और दूसरी तरफ एक कमजोर टीम है जो बिखरी हुई है। ऐसे में मुकाबला एकतरफा दिखता था, और लगता था कि बस देखना यही है कि भाजपा अपने विरोधियों को कितने अंतर से हराएगी। लेकिन, जैसे-जैसे विपक्षी दल संगठित हो रहे हैं या होने का प्रयास कर रहे हैं, और अब जब उन्हें एक मुद्दा मिल गया है जो अपने आप में एक बड़ा पैकेज है, तो 2024 का मुकाबला अब पहले के मुकाबले ज्यादा रोमांचक बन गया है। बिहार की जातीय गणना केवल बिहार का मुद्दा नहीं है। इसे लेकर विपक्षी पार्टियां भाजपा की सरकार वाले राज्यों में दबाव बनाने का प्रयास करेंगी। वे बिहार के आंकड़ों को लेकर उन राज्यों के ओबीसी वोटरों तक पहुंचने और भाजपा को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेंगी।

# विधानसभा चुनावों में छोटे दल बढ़ाएंगे बड़े दलों की मुश्किलें !

**राजकुमार सिंह**

लोकसभा चुनाव से पहले इसी साल विधानसभा चुनाव तो पांच राज्यों में होने हैं लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर ही निगाहें इसलिए टिकी रहेंगी, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के बीच वहां सत्ता के लिए सीधा मुकाबला होता है। इसलिए भी कि इन तीनों राज्यों की सत्ता कांग्रेस ने पिछले चुनाव में भाजपा से छीन ली थी। राजस्थान में पिछले तीन दशक में भाजपा-कांग्रेस के अदल-बदल कर सत्ता में आने का रिवाज-सा बन गया है। कभी तीसरी ताकत रही जनता पार्टी और जनता दल अब इतिहास की बात हैं। फिर भी कुछ छोटे दल हैं, जो सत्ता के मुख्य दावेदारों के दिलों की धड़कनें बढ़ा देते हैं। पिछली बार 200 सदस्यीय विधानसभा में 73 सीटों के साथ भाजपा तो सत्ता की दौड़ में बहुत पीछे छूट गई थी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा (101) कांग्रेस भी नहीं छू पाई थी। अशोक गहलोत की जादूगरी भी कह सकते हैं कि बसपा के छह, माकपा के दो और 12 निर्दलीयों के बीच जुगाड़ से कांग्रेस सत्ता के पांच साल पूरे कर रही है। एकमात्र रालोद विधायक सुभाष गर्ग तो बाकायदा मंत्री हैं। इस बार रिवाज बदलना या न बदलना कई बातों पर निर्भर करेगा। मसलन, अभी तक लड़ते रहे गहलोत-सचिन पायलट की सुलह चुनाव में कितनी वास्तविक रहेगी? दो बार मुख्यमंत्री रहीं वसुंधरा राजे के असंतोष और मान-मनौव्वल अंतिम क्षणों तक चल सकते हैं, पर बड़ी चुनौती वे छोटे दल हैं, जो सत्ता के दावेदार नहीं हैं, पर बहुमत का दारोमदार उन पर निर्भर कर सकता है। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) किसान आंदोलन से पहले तक एनडीए में थी। अब अलग ताल ठोंक रही रालोपा का जाट समुदाय में कुछ असर है। भाजपा ने नागौर से कांग्रेस सांसद रह चुकीं ज्योति मिर्धा को शामिल कर समीकरण साधने की कोशिश की है। बेशक सपा और रालोद 'इंडिया' का अंग हैं, पर सीटें तो मांगेंगे। बसपा की राजनीतिक माया समझ पाना हमेशा मुश्किल रहा है। सबसे दिलचस्प होगी आप की भूमिका, जो 'इंडिया' में है, पर उसके मंसूबे बड़े हैं। उसकी मांग पूरी कर पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। मित्रवत मुकाबले में आप किसे नुकसान पहुंचाएगी-यह गुजरात और गोवा से समझा जा सकता है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा (116) नहीं छू पाई थी। उसे 114 सीटें मिली थीं। चार निर्दलीय और सपा-बसपा के क्रमशः एक-दो विधायक जीते। कमलनाथ, गहलोत जैसी जादूगरी नहीं दिखा पाए और 15 महीने बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक 22 विधायकों की बगावत से सत्ता में शिवराज सिंह चौहान की वापसी हो गई। अब मतदाता किसका साथ देंगे?

# कभी न पूरे होने वाले वादे क्यों करते हैं नेता ?

**राजेश बादल**

भारतीय लोकतंत्र परिपक्व और समझदार हो रहा है। इसे नहीं मानने का कोई कारण नहीं है। साक्षरता का प्रतिशत बढ़ने के साथ-साथ आम मतदाता भी सोच के स्तर पर जागरूक हो रहा है। यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। फिर भी इस जम्हूरियत के साथ कुछ विरोधाभास चिपके हुए हैं। विरोधाभासों का यह गुच्छा सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। यह भारतीय लोकतंत्र में न तो लोक के लिए बेहतर है और न ही तंत्र के लिए। चुनाव के दिनों में तो यह और भी विकराल तथा विकृत स्वरूप में हमारे सामने उपस्थित है। चुनाव से पहले राजनेताओं को पता होता है कि वे जो लालच दे रहे हैं या जो वादे जनता के साथ कर रहे हैं, वे कभी पूरे नहीं होंगे। दूसरी ओर मतदाता भी अब इतना मासूम और भोला नहीं रहा। वह समझता है कि उम्मीदवार, मंत्री और मुख्यमंत्री जो वचन दे रहे हैं या घोषणाएं कर रहे हैं, उनमें से एक प्रतिशत भी पूरी होने वाली नहीं हैं। पर वह क्या करे? दोनों पक्ष हकीकत जानते हुए भी इस व्यवस्था को चलने दे रहे हैं। इस बिंदु पर आकर लोकतांत्रिक सेहत को नुकसान तो होना ही है। पांच प्रदेशों में इन दिनों विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। कभी भी निर्वाचन आयोग तारीखों की घोषणा कर सकता है। इसके बाद आचार संहिता के चलते सरकारी योजनाओं के तहत नए निर्माण, ठेकों, अनुदान और उनके क्रियान्वयन पर विराम लग जाएगा।

पांच में से दो राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें हैं, मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति सत्ता में है और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की हुकूमत है। चुनाव जीतने और अपनी सरकार बचाए रखने के लिए ये दल एड़ीचोटी का जोर लगा रहे हैं। इस होड़ में वे ऐसे-ऐसे वादों को मतदाताओं के सामने रख रहे हैं, जो सिर्फ हवा हवाई हैं। वे कभी भी पूरे नहीं किए जा सकते। यदि उसी दल की सरकार दुबारा बन जाए तो भी ये राजनेता अपने

वादे पूरे नहीं कर सकते। संविधान की शपथ लेकर सरकार चलाने वाले मंत्री और मुख्यमंत्री शायद भूल जाते हैं कि वे पद पर रहते हुए आखिरी पल तक शपथ से बंधे होते हैं। वे जो भी घोषणा करते हैं, उसे पूरा करना उनका संवैधानिक दायित्व है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो यकीनन यह संवैधानिक विश्वासघात की श्रेणी में आता है। कुछ समय पहले एक सर्वेक्षण में पाया गया था कि चुनाव पूर्व घोषणाओं में बमुश्किल चार या पांच फीसदी पर अमल हो पाता है। बाकी सब ठंडे बस्ते में चली जाती हैं।यहां एक पेंच को भी समझना आवश्यक है। चुनाव से कुछ महीने पहले जो वादे किए जाते हैं, घोषणाओं की झड़ी लगाई जाती है, उसमें से नब्बे फीसदी बजट में पास नहीं कराए जाते और न ही बजट का हिस्सा होते हैं।

चुनाव के साल में जो बजट पारित किया जाता है, उसे चुनावी या लोकलुभावन बजट इसीलिए तो कहते थे। राजनीतिक दल अपनी सरकारों को निर्देश देते थे कि चुनावी साल के मद्देनजर मतदाताओं को पसंद आने वाली योजनाओं पर धन आवंटन कर दिया जाए। चुनाव आते-आते वह निर्धारित धन खर्च कर दिया जाता था। नियम तो यह कहता है कि किसी प्रदेश का वित्त विभाग वही धन जारी कर सकता है, जो विधानसभा में पारित बजट का हिस्सा हो। चाहे वह कैसे भी खर्च करने के लिए हो। मगर, देखा गया है कि विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री अपनी ओर से रैलियों में या सभाओं में अपने इलाके की किसी भी समस्या का निदान करने का ऐलान कर देते हैं। चुनाव के बाद हार गए तो कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगता। पार्टी जीत गई तो फिर वह वादा जब तक बजट का हिस्सा नहीं बनता, पूरा नहीं हो पाता। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि आपात स्थितियों में भी यदि सरकार पैसा खर्च करना चाहे तो उसकी निर्धारित प्रक्रिया होती है। घोषणा से पहले मंत्रिमंडल की मंजूरी अनिवार्य है। मंत्रिमंडल की औपचारिक मंजूरी के बाद इसका गजट नोटिफिकेशन होता है। उसके बाद ही वित्त विभाग धन जारी कर सकता है। पर यह भी नहीं होता। हाल के दिनों में हमने यह भी देखा है कि निर्धारित प्रक्रिया और राजकोष में जमा खजाने की समीक्षा किए बिना ही अनेक प्रदेश जनता को लुभाने के लिए अनाप-शनाप पैसा खर्च करने लगते हैं। इसके लिए भी वे हर महीने ऋण भी लिया करते हैं। मध्यप्रदेश में अनेक योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो पा रहीं क्योंकि विभागों के पास पैसा ही नहीं है। वेतन बांटने के लिए सरकार प्रत्येक माह लगभग तीन से पांच हजार करोड़ रु कर्ज लेती है। कर्ज लेने की यह प्रवृत्ति विकास की प्राथमिकताओं को प्रभावित करती है। विडंबना है कि चुनाव के बाद जो भी पार्टी सरकार बनाती है, वह कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस चुकी होती है। कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? सियासत में बढ़ती अनैतिकता आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक संकेत दे रही है। चुनाव आयोग इसमें चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। सवाल यह है कि इस बीमारी का इलाज क्या है। हिंदी के विद्वान चिंतक और विचारक राजेंद्र माथुर कहते थे कि भारत में जब तक उपभोक्ता संस्कृति के साथ-साथ मतदाता संस्कृति नहीं पनपती, तब तक चुनाव प्रक्रिया में दाखिल इन कुरीतियों का समाधान नहीं मिल सकता। मतदाता संस्कृति से उनका आशय यही था कि हर गांव, कस्बे और शहर के मतदाता अपने क्षेत्र के नेताओं की चुनावी घोषणाओं का दस्तावेजीकरण करें और उनके जीतने पर इलाके के बाहर एक बड़े बोर्ड में उन्हें लिख दिया जाए। जब नेताजी आएं तो उन्हें वह बोर्ड दिखाया जाए और जब उन वादों पर अमल हो जाए, तभी उनकी बात सुनी जाए और उन्हें नई घोषणा करने दी जाए। संभवतया इससे कुछ समाधान मिल सके।

# राजस्थान-छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री-सांसदों पर दांव लगाने की तैयारी में भाजपा

**राहुल संपाल**

मध्य प्रदेश की दूसरी सूची जारी होने के बाद भाजपा ने राजस्थान में पहली और छत्तीसगढ़ की दूसरी सूची के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर दी है। दिल्ली हाईकमान दोनों राज्यों के सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने में जुटा है। वही सर्वे के अनुसार भाजपा कमजोर सीटों पर जीत हासिल करने के लिए खास रणनीति तैयारी कर रही है। ऐसी चर्चा है कि, भाजपा मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी केंद्र के दिग्गजों को कमजोर सीटों पर उतारकर जीत हासिल करने का प्रयास कर सकती है। इनमें कुछ केंद्रीय मंत्री और सांसदों के नामों सबसे आगे नजर आ रहे हैं।

## राजस्थान के रण में ये केंद्रीय मंत्री और सांसद उतर सकते हैं

सूत्रों के अनुसार, भाजपा केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को विधानसभा टिकट देने पर विचार कर रही है। तीनों केंद्रीय मंत्रियों को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा पार्टी 5 सांसदों और पूर्व सांसदों को भी विधानसभा चुनाव लड़ाने पर पार्टी विचार कर रही है।

सूत्रों का दावा है कि, पार्टी राजसमंद सांसद दीया कुमारी, जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन राठौड़, पाली सांसद पीपी चौधरी और नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा को विधानसभा चुनाव लड़वा सकती है। पिछले दिनों केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जयपुर दौरे के समय दीया कुमारी समेत कुछ सांसदों को चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा था। बीजेपी केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उन मुश्किल सीटों पर चुनाव लड़ाना चाहती है जिन पर उसे अभी तक जीत नहीं मिल पाई है।

**कैलाश चौधरी**- बाड़मेर से सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं। भाजपा को बाड़मेर में जाट वर्ग को संतुष्ट करने के लिए चेहरे की जरूरत है। पहले बायतू से विधायक भी रह चुके हैं। यहां से फिर बायतू से उतारा जा सकता है। अभी- यह कांग्रेस के खाते में है। **राहुल कस्वां**- चूरू से दूसरी बार सांसद हैं। क्षेत्र में जाट वर्ग में उनके परिवार की अच्छी पैठ है। पिता रामसिंह कस्वां पूर्व में सांसद और माता कमला कस्वां पूर्व में विधायक रही हैं। यहां से सादुलपुर से विधानसभा सीट से प्रत्याशी हो सकते हैं। अभी- इस सीट से विधायक कृष्णा पूनिया मंत्री भी है। **सुखबीर सिंह जौनपुरिया**- टोंक-सवाई माधोपुर से सांसद हैं। वर्ष 2014 के चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक और जाने-माने क्रिकेटर मोहम्मद अजहरूद्दीन को हराया था। पूर्वी राजस्थान में गुर्जर प्रतिनिधित्व को ध्यान में रख रहे हैं। यहां से देवली- उनियारा या कोटपूतली से टिकट संभव ।अभी-यहां से कांग्रेस विधायक है। **बाबा बालकनाथ**- अलवर से दूसरी बार सांसद बने हैं। मस्तनाथ मठ के महंत हैं। हिन्दूत्ववादी चेहरा और यादव समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां से बहरोड़ से चुनाव मैदान में उतारकर यादव समाज को साधा जा सकता है। अभी- इस सीट पर निर्दलीय

विधायक है। **दीया कुमारी**- राजसमंद से सांसद हैं और पहले सवाई माधोपुर से विधायक रह चुकी हैं। विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर संदेश देंगे। यहां से- हवा महल सीट से लड़ाया जा सकता है। अभी- यह सीट कांग्रेस भी कांग्रेस के पास है। **भागीरथ चौधरी**- अजमेर से सांसद हैं। जाट वर्ग से आने वाले चौधरी दो बार किशनगढ़ से विधायक रह चुके हैं। स्थानीय होने के कारण सियासी और सामाजिक पकड़ भी है । यहां से जातिगत समीकरण साधने के इन्हें फिर किशनगढ़ से टिकट दे सकते हैं। किशनगढ़ से निर्दलीय विधायक हैं। **राज्यवर्धन सिंह राठौड़**- ग्रामीण लोकसभा सीट से दूसरी बार सांसद हैं। पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। राजपूत समाज से हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। पार्टी झोटवाड़ा विस क्षेत्र से उम्मीदवार बना सकती है।अभी यह सीट कांग्रेस के पास हैं। **गजेंद्र सिंह शेखावत**- केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा है। हालांकि शेखावत शाह के जयपुर दौरे के दौरान इस चर्चा को खारिज कर चुके हैं। उनका कहना है कि पार्टी ने इस बारे में उनसे कोई चर्चा नहीं की है. सरदारपुरा सीट शेखावत के संसदीय क्षेत्र जोधपुर में है। शेखावत 2019 में जोधपुर संसदीय क्षेत्र से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। हालांकि शेखावत के नाम की चर्चा सरदारपुरा के अलावा जोधपुर संसदीय क्षेत्र की एक और सीट से भी हैं। **अर्जुन राम मेघवाल**- केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को खाजूवाला विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। वर्तमान में इस सीट से राजस्थान कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष गोविंद मेघवाल विधायक हैं। खाजूवाला सीट अर्जुन राम मेघवाल के संसदीय क्षेत्र बीकानेर में आती है।

## छत्तीसगढ़ में इन सांसदों पर पार्टी लगा सकती हैं दांव

राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़ में भी यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि कई सांसदों को टिकट दिया जा सकता है। पार्टी के पांच ऐसे सांसद है जो एक बार से ज्यादा बार विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ चुके है। पार्टी पहले ही दुर्ग से सांसद विजय बघेल को पाटन विधानसभा सीट से टिकट दे चुकी है। बघेल को सीएम भूपेश बघेल के सामने उतारा गया है।

**अरुण साव**- बिलासपुर संसदीय सीट से सांसद हैं। साव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अरुण साव को लोरमी या फिर बिलासपुर से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। बिलासपुर से सांसद होने के कारण साव का प्रभाव कई सीटों पर रहेगा इसलिए उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। **रेणुका सिंह**- केंद्रीय राज्य मंत्री सिंह की विधानसभा चुनाव लड़ाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। वे सरगुजा संसदीय सीट से सांसद हैं। रेणुका सिंह 2003 में विधायक रह चुकी हैं। केन्द्रीय मंत्री बनने के बाद क्षेत्र में उनका जनाधार बढ़ा है जिसे देखते हुए उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। रेणुका को लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का भी अनुभव हैं। वे प्रेम नगर सीट से 2003,2008 में विधायक रह चुकी है। **सरोज पांडेय**- राज्यसभा सांसद पांडेय पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। उनके पास लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों ही चुनाव का अनुभव है। सरोज पांडेय के नाम एक ही समय में महापौर, विधायक और सांसद रहने का रिकॉर्ड है। **विजय बघेल**- विजय बघेल पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। इसके पहले वे तीन बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके है। **संतोष पांडेय**- राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडेय के भी विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। पांडेय कवर्धा जिले के रहने वाले हैं। उन्हें कवर्धा जिले की किसी विधानसभा सीट से उतारा जा सकता है। **गोमती साय**- राय रायगढ़ लोकसभा सीट से सांसद हैं। रायगढ़ जिले की लैलूंगा या फिर सारंगढ़ विधानसभा सीट से उनके उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। **चुन्नीलाल साहू**- महासमुंद सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले साहू पहली बार के सांसद है। लेकिन वे खल्लारी सीट से सांसद विधायक रह चुके है।

# 'द कपिल शर्मा शो' को शैलेश लोढ़ा ने कहा था 'अश्लील'? अब बोले- दादी या बुआ का फ्लर्ट करना हमारी संकृति नहीं

**'तारक मेहता** का उल्टा चश्मा' शो को अलविदा कह चुके शैलेश लोढ़ा ने अब जाकर कपिल शर्मा के शो की आलोचना करने पर सफाई दी है। उन्होंने बताया कि क्यों वह उनके शो में गए थे। साथ ही भाबी जी घर पर हैं शो पर भी उन्होंने रिएक्ट किया है। 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को छोड़ चुके शैलेश लोढ़ा ने कॉमेडी शोज को लेकर रिएक्शन दिया। ऐसे कार्यक्रमों में होने वाली कॉमेडी के बारे में उन्होंने खुलकर बात की। साथ ही 'द कपिल शर्मा शो' की आलोचना करने और खुद ट्रोल होने वाले मुद्दों पर भी उन्होंने रिएक्ट किया। हुआ ये था कि एक वक्त था जब शैलेश लोढ़ा को कपिल शर्मा शो की आलोचना करने और फिर उन्हीं के शो में जाने को लेकर लोगों ने भला बुरा कहा था।

अब 'द लल्लनटॉप' को दिए इंटरव्यू में शैलेश लोढ़ा ने इस पूरे मसले पर जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'मैंने और कपिल शर्मा ने साथ में काम किया है। साल 2012 में मैं और कपिल सिंगापुर में साथ में एक शो कर रहे थे जिसका नाम था 'कॉमेडी नाइट्स विद शैलेश और कपिल'। मेरी बातों को गलत तरह से पेश किया गया। मैंने कहा था कि मुझे बुआ, दादी के साथ फ्लार्टिंग करना पसंद नहीं। ये हमारी संस्कृति नहीं है। मैं खुद ऐसी चीजों में सहज नहीं हूं। आज भी मैं अपनी इस बात पर अडिग हूं।'

**कपिल शर्मा शो पर क्या बोले शैलेश लोढ़ा**

वह आगे कहते हैं, 'लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं कपिल शर्मा के शो में नहीं जाऊंगा या फिर काम नहीं करूंगा। क्योंकि मैंने उनके शो पर ये सब नहीं कहा। हां, मैं उनके शो में गया था और हिंदी कविताओं की मजबूती को रखा भी था।

मैंने जब अपनी कविता 'मां' को सुनाया था तो शो का हर इंसान खड़ा हो गया और सबकी आंखों में आंसू आ गए। कपिल शर्मा एक शानदार इंसान और इंसान हैं। वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं।'

**'भाबी जी घर पर हैं' पर क्या बोले शैलेश लोढ़ा**

इसी इंटरव्यू में शैलेश लोढ़ा 'भाबी जी घर पर हैं' जैसे शोज की कॉमेडी पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि पड़ोसन से फ्लर्ट करना जैसे कई मजाक को लोगों पसंद कर रहे हैं। हर कोई इंटेलीजेंट कॉमेडी न तो कर रहा है न ही देख रहा है। 90% लोग रील देख रहे हैं। अगर आप सीरियस कुछ दिखा भी रहे हैं तो लोग देखना नहीं चाहते।

# क्या प्रभास की 'सालार' है 'उग्रम्म' का रीमेक? म्यूजिक कंपोजर के बयान ने खोल दी पोल-पट्टी

प्रभास की सालार और शाहरुख खान की डंकी क्रिसमस 2023 पर क्लैश हो रही है। इस बीच गॉसिप्स ये चल पड़े हैं कि सालार के डायरेक्टर प्रशांत नील कन्नड़ फिल्म का रीमेक है। आइए दिखाते हैं वो वीडियो, जिसके बाद ये सब गॉसिप्स चल पड़े हैं। आइए वो भी बताते हैं जब प्रशांत नील ने जवाब दिया था कि आखिर क्या है माझरा।

प्रभास की 'सालार' इसी साल 22 दिसंबर 2023 को रिलीज हो रही है। ये वही दिन है जब शाहरुख खान की 'डंकी' भी सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इसका मतलब कि 'सालार' और 'डंकी' का महाक्लैश होगा। अब देखना ये है कि बॉक्स ऑफिस की इस जंग में किसकी जीत होगी और किसकी हार। अब जैसे जैसे 'सालार' की रिलीज डेट नजदीक आ रही है, ऐसे में फिल्म से जुड़ी बड़ी डिटेल में देखने को मिल रही है। अब चर्चा ये चल पड़ी है कि प्रशांत नील की 'सालार' कन्नड़ फिल्म 'उग्रम्म' का रिमेक है। आइए बताते हैं आखिर क्या है पूरा मसला।

'उग्रम्म' को भी प्रशांत नील ने साल 2014

में बनाया था। ये फिल्म इतनी पसंद की गई थी कि इसे उड़िया और मराठी में भी बनाया गया था। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। अब गॉसिप्स ये है कि 'सालार' इसी फिल्म का रीमेक है।

कैसे शुरू हुई 'सालार' के रीमेक की चर्चा

एक इंटरव्यू में 'उग्रम्म' के कंपोजर रवि बसरुर से इस बारे में सवाल किया गया। तब उन्होंने कहा, 'बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लग भी ऐसा ही रहा है। फिलहाल हम लोगों को इंतजार करना होगा। तभी सब चीजें क्लियर हो पाएंगी।' हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ये वीडियो नया है कि पुराना।

उग्रमम ओटीटी पर हैं मौजूद

गॉसिप्स तो ये भी थे कि 'सालार' के चलते मेकर्स ने उग्रमम को यूट्यूब से भी हटा लिया है। लेकिन ये सच नहीं है। फिल्म अभी भी यूट्यूब पर मौजूद है। इसका हिंदी वर्जन जी5 पर भी उपलब्ध है।

**'सालार' के रीमेक वाली बात पर खुद डायरेक्टर ने क्या कहा था**

कुछ समय पहले 'सालार' के डायरेक्टर प्रशांत नील से भी यही सवाल किया गया था कि क्या 'सालार', 'उग्रम्म' का रीमेक है? डायरेक्टर ने कहा था कि आजतक मैंने जो भी फिल्में बनाई हैं वह कहीं न कहीं 'उग्रम्म' के शेड्स हैं। यही मेरा स्टाइल है। मगर सालार फ्रेश स्टोरी है। न तो ये रीमेक है न ही ये कहानी 'उग्रम्म' से मिलती जुलती है।

# आमिर खान ने सनी देओल से मिलाया हाथ 'गदर 2' की तरह बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल?

**बॉलीवुड के मिस्टर** परफेक्शनिस्ट आमिर खान आखिरी बार फिल्म लाल सिंह

चड्ढा में नजर आए थे. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी. इसके बाद स आमिर ने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया है. अब उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर दी है. इस फिल्म में आमिर एक्टिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे बल्कि वह इसे प्रोड्यूस करने जा रहे हैं. इस फिल्म के लिए आमिर ने सनी देओल से हाथ मिलाया है. फिल्म का नाम लाहौर 1947 रखा गया है. इस राजकुमार संतोषी डायरेक्ट करेंगे.

आमिर खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके फिल्म की अनाउंसमेंट की है. आमिर के प्रोडक्शन हाउस ने पोस्ट में लिखा- मैं और एकेपी की पूरी टीम सनी देओल और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के साथ फिल्म लाहौर 1947 की अनाउसमेंट करते हुए बहुत एक्साइटेड हैं. हम टैलेंटिड सनी और मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक राजकुमार संतोषी के साथ कोलेबरेट के लिए बेताब है. हमने जो यात्रा शुरू की है वह सबसे समृद्ध होने का वादा करती है. हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं.

राजकुमार संतोषी और सनी देओल इससे पहले 'घायल', 'दामिनी', और 'घातक' जैसी फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर तीन हिट फिल्में दे चुके हैं. इस इम्प्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, यह अनुमान लगाना जाहिर है कि उनकी आने वाली फिल्म भी किसी एपिस से कम नहीं होगी.

वहीं, जो बात इस घोषणा को और भी खास बनाती है, वह यह है कि सनी देओल और आमिर खान के बीच कॉम्पिटीटर के रूप में आइकॉनिक बॉक्स-ऑफिस क्लैश हुआ है, जहां जीत की फिल्में हिट रहीं. ये क्लैश 1990 में हुआ था. जब आमिर खान की दिल और सनी देओल की घायल एक ही दिन रिलीज़ हुई थीं. फिर 1996 में राजा हिंदुस्तानी वर्सेज घातक के बाद 2001 में भारतीय सिनेमा का सबसे एपिक बॉक्स ऑफिस टकराव हुआ जब लगान उसी दिन गदर के साथ रिलीज़ हुई. और अब पहली बार दोनों ने किसी प्रोजेक्ट पर हाथ मिलाया है.

# 'द वैक्सीन वॉर ' की नाकामी से बौखलाए विवेक अग्निहोत्री, करने लगे प्लेबॉय और भगवद गीता की तुलना

विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई है। फिल्म को फ्लॉप बताया जा रहा है। हालांकि फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद विवेक अग्निहोत्री ने अपनी मूवी को मास्टरपीस बताया था। अब फिल्म की नाकामी के बाद वह भगवद्गीता का जिक्र करते नजर आ रहे हैं।

ओपनिंग डे पर मात्र 85 लाख का कारोबार

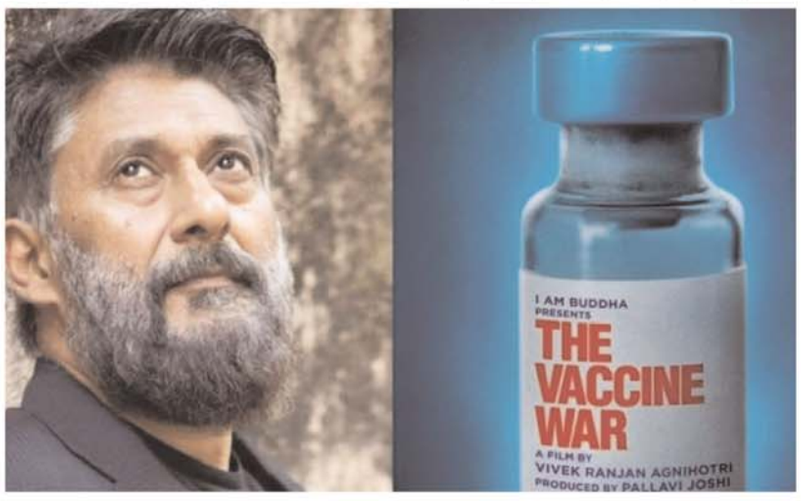


करने वाली द वैक्सीन वॉर लंबे वीकेंड का भी फायदा नहीं उठा पाई। फिल्म दर्शकों के लिए तरसती ही दिखी। वहीं इसी के साथ रिलीज फिल्म फुकरे बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। द वैक्सीन वॉर ने रिलीज के चार दिन बात भी कमाई में 6 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं किया।

**'द वैक्सीन वॉर' पर क्या बोले डायरेक्टर?**

बॉक्स ऑफिस के नतीजे और ट्रेड पंडित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर को सुपर फ्लॉप बता रहे हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में विवेक ने अपनी ताजा फिल्म का बचाव करते दिखे। उन्होंने ने कहा कि उनकी फिल्म जितने लोग भी देखने गए उनमें से 90 प्रतिशत को वह पसंद आई। किसी ने फिल्म के लिए नेगेटिव रिव्यू नहीं दिया। बकौल विवेक जितने लोगों ने भी फिल्म देखी वो सब एक गर्व की भावना के साथ थियेटर के बाहर निकले। उनकी आंखों में आंसू दिखे। विवेक ने कहा कि ऐसा सोचते हैं तो उन्हें अपनी सोच बदलनी होगी। फिल्म की नाकामी का दर्द विवेक के इंटरव्यू पर साफ दिखाई दिया। उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान को एक छिछली फिल्म बताते हुए अपनी मूवी द वैक्सीन वार को शानदार बताया। विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि जवान फिल्म निर्माण के क्षेत्र में बेहद सतही मूवी है।

**पिछली फिल्म हुई थी जबरदस्त हिट**

बता दें कि द वैक्सीन वॉर से पहले विवेक की पिछले साल द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी। साल 2022 मे रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। उसके लिए विवेक अग्निहोत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। फिल्म को माउथ पब्लिसिटी और राजनीति का बेहद लाभ मिला था। हालांकि द वैक्सीन वॉर के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मूवी बॉलीवुड की फ्लॉप फिल्मों में दर्ज हो चुकी है।

**गीता और प्लेबॉय की करने लगे तुलना**

बदतर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर विवेक अग्निहोत्री ने ट्रेड एनालिस्ट्स पर भी सवाल उठाया। डायरेक्टर ने उनसे पूछा कि क्या जितने प्लेबॉय खरीदते हैं उतने लोग गीता भी खरीदते हैं। ऐसा तो होता नहीं है। वह अगर

# सलमान खान के सिनेमा में 35 साल पूरे, 'भाईजान' ने टाइगर 3 को फैंस के लिए बताया रिटर्न गिफ्ट

बड़े पर्दे पर अब तक के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक, सलमान खान, टाइगर 3 के साथ सिनेमा में अपने 35 साल का जश्न मनाने के लिए उत्साहित हैं, जिसे आदित्य चोपड़ा की यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित किया गया है।

सलमान खान कहते हैं, "जिन लोगों ने मुझे मेरे डेब्यू के बाद से प्यार किया है, उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पर एहसास कराया कि मैंने सिनेमा में 35 साल पूरे कर लिए हैं! यह मेरे लिए एक बहुत ही खास पल है, पुरानी यादों, प्यार, बहुत खुशी और उस दर्द से भरा हुआ जब चीजें योजना के अनुसार नहीं हुईं। लेकिन मुझे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जर्नी का हर मिनट पसंद आया है।"

उन्होंने आगे कहा, "टाइगर 3 की रिलीज के साथ इस व्यक्तिगत मील के पत्थर का जश्न मनाते हुए मुझे खुशी हो रही है। मुझे पता है कि मेरे प्रशंसक मुझे एक्शन करते हुए देखना पसंद करते हैं और मुझे उम्मीद है कि टाइगर 3 एक आदर्श उपहार है जिसका वे इंतजार कर रहे थे।"

सलमान टाइगर 3 के पहले वीडियो एसेट, टाइगर का मैसेज को दुनिया भर के दर्शकों से मिल रही प्रतिक्रिया से बेहद उत्साहित हैं। यशराज फिल्म्स ने पिछले हफ्ते टाइगर का मैसेज जारी किया जो इंटरनेट पर तुरंत ब्लॉकबस्टर हो गया था।

यशराज फिल्म्स अपनी फिल्मों की मार्केटिंग काफी अनूठे तरीके से करता है। टाइगर 3 के इस वीडियो से पहले किसी और फिल्म के साथ ऐसा नहीं किया गया है। टाइगर का मैसेज रिलीज करने के बाद से फिल्म की रीच

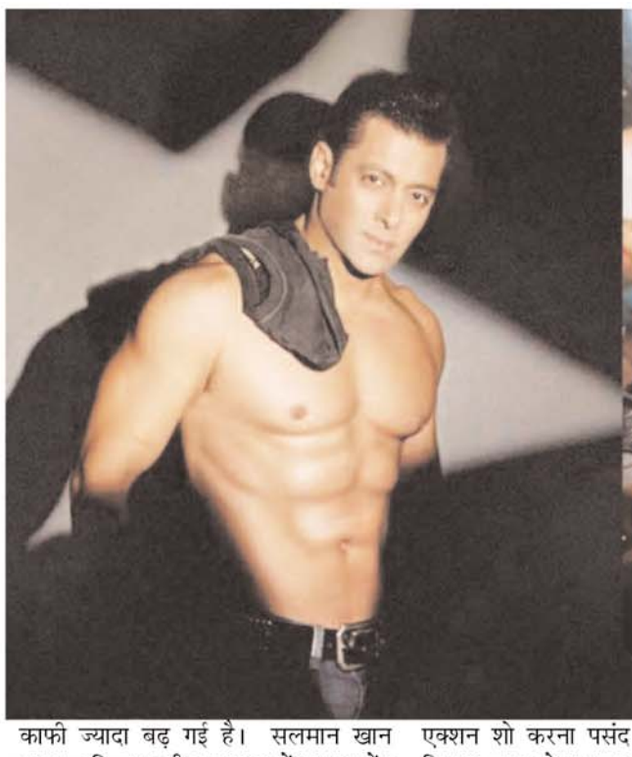

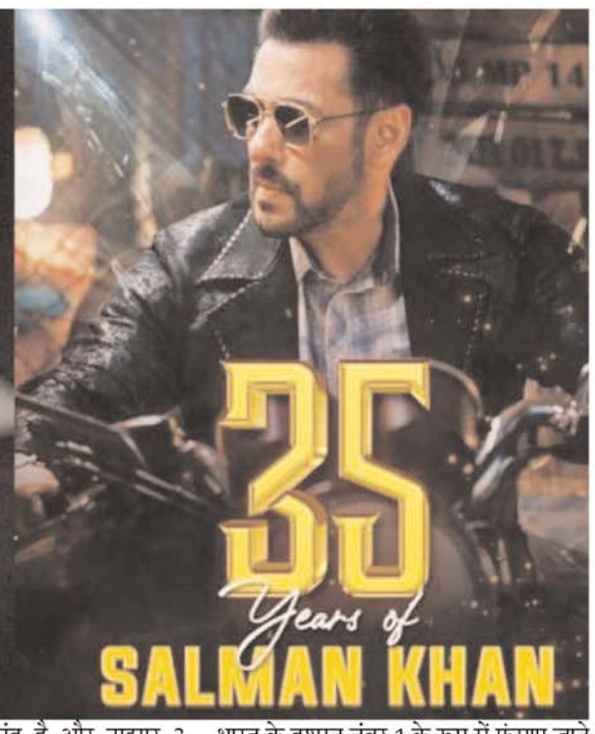


काफी ज्यादा बढ़ गई है। सलमान खान यशराज फिल्म्स की टाइगर 3 में सुपर एजेंट टाइगर उर्फ अविनाश सिंह राठौड़ के रूप में अपनी बहुचर्चित भूमिका को दोहराने के लिए वापस आ गए हैं। भारतीय सिनेमा के मेगास्टार का कहना है कि उन्हें फिल्मों में लार्जर दैन लाइफ हीरो बनना पसंद है।

सलमान कहते हैं, "मुझे एक्शन जॉनर पसंद है, मुझे लार्जर दैन लाइफ एक्शन स्टार बनना पसंद है। मजा आता है! मुझे बड़े एक्शन शो करना पसंद है और टाइगर 3 जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा है। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है जो मुझे बहुत पसंद आई और मुझे यकीन है कि हम इससे सभी को चौंका देंगे।"

वाईआरएफ के घरेलू फिल्ममेकर मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित टाइगर 3, इस साल बड़ी दिवाली छुट्टियों पर रिलीज होने के लिए तैयार है!

टाइगर के मैसेज में खुलासा किया गया कि भारत के दुश्मन नंबर 1 के रूप में फंसाए जाने के बाद सलमान उर्फ टाइगर खतरे में हैं। यह वीडियो फिल्म की कहानी तैयार करता है जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे टाइगर इस प्रतिशोधपूर्ण एक्शन मनोरंजक फिल्म में अपने दुश्मनों का शिकार करने के लिए एक जानलेवा मिशन पर निकलता है। टाइगर अपने देश, अपने परिवार के लिए अपना नाम साफ़ करना चाहता है और वह किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा।

# नेचुरल नहीं थी श्रीदेवी की मौत : बोनी कपूर

90 के दशक की बेहतरीन अदाकारा श्रीदेवी आज भले ही इस दुनिया में नहीं हैं मगर, वो आज भी अपने अभिनय और खूबसूरती की वजह से लोगों के जहन में हैं। एक्ट्रेस की फैन फॉलोइंग ना केवल देश में थी बल्कि विदेशों मेंभी थी। लोग उनकी एक झलक पाने का बेसब्री से इंतजार करते थे लेकिन, उनकी मौत की खबर ने फैंस क्या हर किसी को हिला कर ही रख दिया था। 24 फरवरी, 2018 को वो दुनिया को अलविदा कह गईं। उनकी मौत को 5 साल हो चुके हैं लेकिन, आज भी लोग ये जानने के लिए बेताब हैं कि आखिर उनकी मौत कैसे हो गई। इसकी असल वजह क्या थी? मौत की वजह को लेकर पहले काफी खबरें सामने आ चुकी हैं लेकिन, अब उनके पति बोनी कपूर ने निधन की असली वजह का खुलासा किया है। चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कहा?

फिल्म निर्माता और दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी के पति बोनी कपूर पिछले पांच सालों से पत्नी के निधन की वजह पर 5 सालों से चुप्पी बनाए हुए थे लेकिन अब जाकर उन्होंने इस पर बात की है। उन्होंने इंटरव्यू में इसका खुलासा किया है उनका कहना है कि श्रीदेवी की मौत नेचुरल नहीं थी। ये एक आकस्मिक मौत थी। बोनी ने बताया कि उन्होंने इस बारे में ना बोलने का फैसला किया था। एक्ट्रेस की मौत को लेकर उनसे 24 या 48 घंटों तक पूछताछ की गई थी। वो इस मामले को लेकर लाई डिटेक्टर टेस्ट तक से गुजर चुके थे, इस केस में जो भी रिपोर्ट सामने आई थी वो बताती हैं कि ये एक आकस्मित मौत थी।

**आंखों के आगे छा जाता था अंधेरा- बोनी कपूर**

बोनी कपूर ने इंटरव्यू में एक्ट्रेस की मौत की वजह को लेकर आगे बताया कि वो अक्सर भूखी रहती थीं। निधन के समय भी वो डाइट पर थीं। वो अच्छा दिखना चाहती थीं, जिसके चलते स्पेशल डाइट प्लान फॉलो करती थीं और अक्सर भूखी रहती थीं। बोनी बताते हैं कि जब से उनकी उनसे शादी हुई थी तब से उन्हें कुछ मौकों पर ब्लैकआउट (आंखों के आगे अंधेरा हो जाना) की समस्या हुई और डॉक्टर भी उनसे कहते रहे की उन्हें लो बीपी की समस्या है।

**जब टूट गए थे श्रीदेवी के दांत**

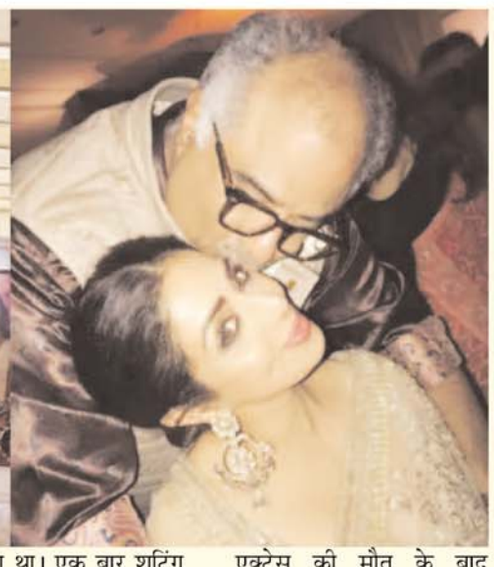

इतना ही नहीं बोनी कपूर आगे श्रीदेवी से जुड़ी एक घटना का भी जिक्र करते हैं, जिसे नागार्जुन ने शेयर किया था। एक बार शूटिंग के दौरान वो बाथरूम में बेहोश हो गई थीं।

एक्ट्रेस की मौत के बाद नागार्जुन संवेदनाओं के साथ उनके घर गए थे। तब उन्होंने बोनी कपूर के साथ फिल्म की शूटिंग के दौरान का किस्सा शेयर किया था। वो एक फिल्म के दौरान फिर से क्रैश डाइट पर थीं और इसी तरह वो बाथरूम में गिर गई थीं और उनके दांत टूट गए थे।

इसके साथ फिल्ममेकर ने ये भी बताया कि शादी के बाद उन्हें श्रीदेवी की स्ट्रीक्ट डाइट के बारे में पता चला था। बोनी कपूर अक्सर एक्ट्रेस से रात के खाने में नमक वाला खाना खाने का अनुरोध करते थे।

नमक को लेकर उन्होंने कई बार डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट की थी वो उन्हें रात के खाने में नमक वाला खाना खाने की सलाह दें लेकिन लेकिन श्रीदेवी ने कभी भी इसे गंभीरता नहीं लिया था।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

## पीएम मोदी आज मध्यप्रदेश और राजस्थान जाएंगे

**नईदिल्ली।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को चुनावी राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान, वह दोनों राज्यों में 17,600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने बुधवार को एक बयान में यह जानकारी दी है। पीएमओ के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में लगभग 5,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा क्षेत्रों से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), जोधपुर परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इसके साथ ही जोधपुर हवाई अड्डे पर नये टर्मिनल भवन तथा वहां स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की आधारशिला रखेंगे।

## आप सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी का छापा

**नईदिल्ली।** दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर तलाशी ली। इससे पहले मामले में सांसद के कई अन्य करीबी लोगों के परिसरों की तलाशी ली गई थी। शराब नीति मामले में दायर आरोपपत्र में संजय सिंह का नाम था। तलाशी पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय सिंह के पिता ने कहा कि विभाग अपना काम कर रहा है, हम उनके साथ सहयोग करेंगे। मैं उस समय का इंतजार करूंगा जब उन्हें मंजूरी मिलेगी। इस बीच, पार्टी ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी संसद में अडानी मामले को उठाने के लिए सिंह को निशाना बना रही है। शिवसेना (यूबीटी) की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा कि एनडीए में बीजेपी के एकमात्र आश्रित सहयोगी ईडी, आईटी, सीबीआई हैं। संजय सिंह के घर पर की जा रही छापेमारी की निंदा करें, यह डराने-धमकाने की रणनीति के अलावा और कुछ नहीं है।

## केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य सरगना हैं : भाटिया

**नईदिल्ली।** भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने साफ तौर पर कहा कि देश और दिल्ली की जनता जानती है कि शराब घोटाले के मुख्य सरगना अरविंद केजरीवाल है, उन्हीं के इशारे पर दिल्ली में ये शराब घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की साढ़ेसाती कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल पर भी असर कर रही है। आज संजय सिंह के यहां भी जांच एजेंसियों ने छापा मारा है। उन्होंने बताया कि 3 तथ्य बहुत ही चिंताजनक है- एक आरोपी दिनेश अरोड़ा ने कबूला है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर शराब कारोबारियों की एक बैठक हुई। वहां कमीशन तय हुआ। भाजपा नेता ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर संजय सिंह कहते हैं कि 32 लाख रुपये पापी आप यानि अराजक अपराध पार्टी के कोष में दो। एक सांसद मुख्यमंत्री के आवास पर बैठकर वसूली करता है। ये बहुत चिंताजनक है। तंज भरे लहजे में भाटिया ने कहा कि केजरीवाल ने जिसे कट्टर ईमानदार का प्रमाणपत्र दिया, वो पूर्व उपमुख्यमंत्री कट्टर बेईमान निकला। मैं चुनौती देता हूं कि आप ये बात नकारें की आपने ये 32 लाख की रिश्वत नहीं ली है।

## शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक और पत्नी रुचिरा को समन

**कोलकाता।** प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को तलब किया है। अभिषेक को 9 अक्टूबर को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है और उनकी पत्नी को 11 अक्टूबर को बुलाया गया है। यह पहली बार है जब ईडी ने भर्ती घोटाले में रुजिरा को समन जारी किया है। ईडी ने इससे पहले 13 सितंबर को मामले के संबंध में बनर्जी से लगभग नौ घंटे तक पूछताछ की थी। यह मामला पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में विभिन्न अवैध नियुक्तियों की व्यवस्था करने के लिए उम्मीदवारों से कथित तौर पर रकम वसूलने से संबंधित है। जांच एजेंसी के अनुसार, अभिषेक बनर्जी के पिता, अमित बनर्जी, लीप्स एंड बाउंड प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक थे और उनकी पत्नी रुजिरा लीप एंड बाउंड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड की निदेशक थीं।

## दिल्ली की अदालत ने दी लालू राबड़ी और तेजस्वी को जमानत

**नयी दिल्ली।** दिल्ली की एक अदालत ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे एवं बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बुधवार को जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने आरोपियों को उनके खिलाफ जारी समन के अनुपालन में अदालत में पेश होने के बाद यह राहत दी। अदालत ने 22 सितंबर को लालू, राबड़ी, तेजस्वी और अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेने के बाद उन्हें तलब किया था और कहा था कि साक्ष्य प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी सहित विभिन्न अपराधों को अंजाम दिए जाने की तरफ इशारा करते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित घोटाले के संबंध में तीन जुलाई को आरोप पत्र दायर किया था। यह जांच एजेंसी द्वारा मामले में दायर किया गया दूसरा आरोप पत्र था।

### भू-माफिया, खनन एवं अन्य माफिया के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश

# गो तस्करी-धर्मांतरण पर सख्त योगी

**बस्ती।** मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि विवादों एवं जनसमस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता पर करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। मण्डलायुक्त सभागार में बुधवार को आयोजित मण्डलीय समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनप्रतिनिधियों से नियमित संवाद रखें। बस्ती मंडल के तीनों जनपदों (बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर) की समीक्षा के दौरान उन्होंने इन जिलों के जनप्रतिनिधियों को अटल आवासीय विद्यालय का भ्रमण कराने के लिए निर्देश दिया। वहीं उन्होने भू-माफिया, खनन एवं अन्य माफिया के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी कमजोर, गरीब, उद्यमी, व्यवसायी की भूमि पर कोई कब्जा ना करने पाए। सीएम ने शहर के प्रमुख स्थानों और बाजारों में सड़क की ओर फेस करते हुए सीसीटीवी कैमरे लगवाने के भी अधिकारियों को निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने बस्ती मंडल की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सम्पूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस को गम्भीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारी इसका निरीक्षण करें। उन्होने कहा कि पैमाइश एवं नामांतरण के मामलों को गम्भीरता से लेते हुए 48 घण्टे के भीतर निस्तारित करें। मण्डल, जिला, तहसील स्तर पर ऐसे मामलों की समीक्षा की व्यवस्था बनायी जाए। अन्य विभागों के मामलों के निस्तारण की स्थिति की नियमित समीक्षा की जाय, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगी। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद में कोई घटना होने पर संबंधित जनपद एवं तहसील की जिम्मेदारी तय की जायेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित मिशन शक्ति के अन्तर्गत अभियान 14 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। अधिकारी धर्मान्तरण, गो तस्करी, लवजिहाद के मामलों को गम्भीरता से लें। नेपाल से जुड़ी सीमा पर विशेष निगरानी रखें। सभी साईबर थाना एवं साईबर हेल्पडेस्क सक्रिय रखें। नगरपालिकाओं व नगरपंचायतों को सेफ सीटी के रूप में तैयार करें। उन्होने मण्डल के तीनों जिलों के अधिकारियों से संचारी रोग-डेंगू, चिकुनगुनिया, कालाजार, मलेरिया, फाइलेरिया आदि रोगों के बारे में जानकारी ली और निर्देश दिया कि सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपचार की मुकम्मल सुविधा उपलब्ध करायें। इस माह संचालित अभियान के दौरान विशेष स्वच्छता

अभियान संचालित करें। विद्यालयों में प्रार्थना के समय रोगों से बचाव की जानकारी दें। उन्होने जनपदों में डाक्टरों एंव दवाओं की उपलब्धता की भी जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए पात्र व्यक्तियों का चयन करें। प्रथम किस्त जारी होने के बाद समय से गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित कराएं तथा सुनिश्चित करें कि दूसरी किस्त भी समय से जारी हो जाए। जिन पात्र व्यक्तियों के पास भूमि नही है, उन्हें भूमि का पट्टा आवंटित करें। उन्होने कहा कि ग्राम पचायत निधि के उपयोग के बारे में निर्धारित कार्ययोजना लागू करें। सीएम योगी ने दीपावली के पहले सभी सड़कों को गड्ढामुक्त कराने के निर्देश दिये। इसके अलावा विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

बैठक के उपरान्त मुख्यमंत्री ने महर्षि वशिष्ठ चिकित्सा महाविद्यालय ओपेक कैली अस्पताल पहुंचकर इमरजेन्सी वार्ड, एलो जोन तथा रेड जोन का औचक निरीक्षण किया। उन्होने वहां भर्ती मरीजों से वार्ता की तथा उपचार एवं सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। मरीजों द्वारा बताया गया कि उपचार एवं सुविधा बेहतर ढंग से मिल रहा है। उन्होने मेडिकल कालेज में बैच तथा संचालित कोर्स के बारे में जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री राकेश संचान, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी, विधायक अजय सिंह, मण्डलायुक्त अखिलेश सिंह, आईजी आरके भारद्वाज, जिलाधिकारी अंद्रा वामसी, पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी, प्रधानाचार्य डॉ मनोज कुमार, अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉ नीरज पाण्डेय, सीएमएस डॉ एएन प्रसाद, एचओडी डॉ अनिल यादव सहित संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

### सीएम योगी ने की प्रबुद्धजनों से मुलाकात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस सभागार में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्धजनों से मुलाकात की। उन्होंने सभी से अपील की कि समाज एवं जिले की खुशहाली के लिए वे रचनात्मक योगदान करते रहें। उन्होंने केले की खेती को बढ़ावा देने के लिए तथा कंपोज्ट खाद के उत्पाद पर बल दिया। उन्होने कहा कि निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क विकसित करने वाले उद्यमियों को शासन द्वारा पूर्ण सहायता दी जाएगी।

## छत्तीसगढ़ के किसान आज सबसे ज्यादा खुशहाल हैं : सिंहदेव

रायगढ़ में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सहित सभी अतिथियों का हमारी इस पावन धरा में स्वागत करते हैं। आज भरोसे का सम्मेलन रायगढ़ में हो रहा है। यह भरोसा है किसानों का, जिन्होंने हम पर भरोसा किया कि उनकी धान की फसल के 25 सौ रुपए क्विंटल देंगे। हमे खुशी है कि हम उनके भरोसे पर खरे उतरे। किसानों की मांग के अनुसार इस वर्ष 20 क्विंटल खरीदने की घोषणा की है। आज किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। जिसका लाभ व्यापारी और अन्य वर्ग को मिल रहा है। पैसा बाजार में वापस आ रहा है। रायगढ़ में पिछले 5 सालों में ट्रैक्टर खरीदी का रिकॉर्ड बना है। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क से ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा मिला है। छत्तीसगढ़ के युवा को आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल राजीव गांधी युवा मितान क्लब के जरिए किया है। भरोसे के सम्मलेन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और सभी वर्ग के लोगों के लिए अच्छा काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के किसान आज सबसे ज्यादा खुशहाल हैं। पूरे देश में किसानों के हित के लिए जैसी नीतियां छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनाई है वैसी अब तक किसी राज्य ने नहीं अपनाई ना ही हिम्मत कर पाया।

### कांग्रेस पर हमला करते हुए नड्डा बोले- राजस्थान को किया जा रहा बदनाम

# प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति की संस्कृति बदल दी : नड्डा

- भाजपा अध्यक्ष ने जयपुर में सुझाव आपका, संकल्प हमारा अभियान का शुभारंभ किया

**जयपुर।** राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा अपनी पूरी ताकत लगा रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नेड्डा आज जयपुर में सुझाव आपका, संकल्प हमारा अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान नड्डा ने कहा कि सुझाव आपका, संकल्प हमारा अभियान के अंतर्गत 15 दिन में 200 विधानसभाओं में जाना है। वहां लोगों से संपर्क करना और लाखों कार्यकर्ताओं के माध्यम से राजस्थान को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ हमें चलना है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने तय किया है कि किसी का भी सुझाव हम न छोड़ें। मुझे विश्वास है कि ये कार्यक्रम सफल होगा और अपना राजस्थान आपके सुझाव से एक मजबूत और विकसित राज्य बनेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा जब कोई संकल्प पत्र निकालती है, तो वह केवल राजनीतिक दस्तावेज ही नहीं होता बल्कि वह हमारा आगे कार्य करने का लक्ष्य होता है।

नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक राज किया। लेकिन इनका राज ऐसा था कि वादे करो, फिर भूल जाओ और जनता से नए और लुभावने वादे करके अगले चुनाव में फिर खड़े हो जाओ। लेकिन मोदी जी ने इस संस्कृति को बदला और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू की। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ा हुआ है।

उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन हमारे विरोधी कहते थे कि तिथि कब बताएंगे? अब मैं उनसे कहता हूं कि जनवरी में उद्घाटन है, आप जरूर आएंगे। उन्होंने हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का मकसद केवल लूट, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण करना है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा लक्ष्य गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा और किसानों को ताकत और मजबूती देने का है।

अपने तंज में नड्डा ने कहा कि 5 साल तक तो राजस्थान सरकार में खींचातानी चलती रही। इन्होंने विधायकों को अपनी तरफ खींचने के लिए दे दी थी हर तरह की छूट, जिससे उन्होंने मचाई यहां हर तरह की लूट। यहां पिछले 6 महीने में 3 हजार से ज्यादा रेप के मामले सामने आए। अशोक गहलोत राजस्थान को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, बलात्कार के मामलों में राजस्थान पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति की संस्कृति बदल दी। लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, वे राज कैसा था? वायदे करो, बेवफा हो जाओ, भूल जाओ और फिर नए वायदे लेकर अगले चुनाव में खड़े हो जाओ... मोदी जी ने संस्कृति को बदला और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू की, जो कहा है वो करेंगे। जो करेंगे उसको आगे बढ़ाएंगे। अब ऐसी संस्कृति आ गई कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वे भी करके दिया है।

खेल
प्रमुख समाचार

## भारत ने एशियाई खेलों में रचा इतिहास, 71 पदक जीते

**हांगझोउ।** हांगझोउ में खेले जा रहे एशियाई खेलों 2023 में भारत ने बुधवार को इतिहास रच दिया है। भारत ने 71 मेडल जीतकर 2018 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 16 गोल्ड, 26 सिल्वर और 29 कांस्य की मदद से भारत के खाते में अबतक कुल 71 पदक आ चुके हैं। भारत ने 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में कुल 70 पदक जीते थे। भारत ने आज दो पदक अपने नाम किए। 35 किमी पैदल चाल की मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया, तो भारतीय तीरंदाजों देवताले-ज्योति ने कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि एशियाई खेलों में भारत पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा है। 71 पदकों के साथ, हम अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ पदक तालिका का जश्न मना रहे हैं, जो हमारे एथलीटों के अद्वितीय समर्पण, धैर्य और खेल भावना का प्रमाण है। प्रत्येक पदक कड़ी मेहनत की जीवन यात्रा को उजागर करता है। और जुनून। पूरे देश के लिए गर्व का क्षण। हमारे एथलीटों को बधाई।

एशियाई खेलों के पदक तालिका में भारत 16 गोल्ड, 26 सिल्वर और 29 कांस्य के साथ कुल 71 जीतकर नंबर चार पर बना हुआ है। जबकि नंबर वन चीन ने अबतक 164 गोल्ड, 90 सिल्वर और 46 कांस्य की मदद से कुल 300 मेडल जीत लिए हैं। रिपब्लिक कोरिया 32 गोल्ड, 43 सिल्वर और 65 कांस्य की मदद से कुल 140 मेडल जीतकर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। तीसरे स्थान पर जापान है, जिसने 33 गोल्ड, 45 सिल्वर और 50 कांस्य की मदद से कुल 131 मेडल जीत लिए हैं। पांचवें स्थान पर उज्बेकिस्तान है, जिसने 14 गोल्ड, 15 सिल्वर और 21 कांस्य की मदद से कुल 50 मेडल अपने नाम किया है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

## शेयर बाजार में दूसरे दिन सेंसेक्स 286 अंक और लुढ़का

**नईदिल्ली।** घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा और बीएसई सेंसेक्स 286 अंक के नुकसान में रहा। विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी जारी रहने और अमेरिकी तथा एशियाई बाजारों के कमजोर रुख से भी बाजार धारणा प्रभावित हुई। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 286.06 अंक यानी 0.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 65,226.04 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 633.33 अंक तक लुढ़क गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 92.65 अंक यानी 0.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 19,436.10 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में एक्सिस बैंक में सबसे ज्यादा चार प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक, एनटीपीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील, मारुति और लार्सन एंड टुब्रो प्रमुख रूप से नुकसान में रहे।

## एनआईआईएफ ने शुरू किया 60 करोड़ डॉलर का भारत-जापान फंड

**नईदिल्ली।** राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) ने 60 करोड़ डॉलर का भारत-जापान फंड शुरू करने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) के साथ भागीदारी की है। इस फंड में जेबीआईसी और भारत सरकार एंकर निवेशक रहेंगे। वित्त मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी बयान में कहा गया है कि यह फंड पर्यावरण स्थिरता और कम कॉर्बन उत्सर्जन की रणनीतियों में निवेश पर केंद्रित होगा। इसके अलावा यह भारत में जापान के निवेश को और बढ़ाने के लिए ''पसंद के भागीदार' की भूमिका भी निभाएगा। यह एनआईआईएफ का पहला द्विपक्षीय फंड है। इसमें भारत सरकार 49 प्रतिशत और जेबीआईसी 51 प्रतिशत का योगदान देंगे।

## ब्रिटेन की 'सुपरड्राई' दक्षिण एशिया की आईपी संपत्तियां रिलायंस को बेचेगी

**नईदिल्ली।** ब्रिटेन की फैशन क्षेत्र की खुदरा कंपनी 'सुपरड्राई' दक्षिण एशिया में अपनी बौद्धिक संपदा संपत्तियां रिलायंस रिटेल को चार करोड़ पाउंड (402 करोड़ रुपये) में बेचेगी। यह सौदा एक संयुक्त उद्यम के जरिये होगा। सुपरड्राई के फैशन उत्पादों में स्वेटशर्ट, हुडी और जैकेट शामिल हैं। इसकी संयुक्त उद्यम में 24 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। शेष 76 प्रतिशत हिस्सेदारी रिलायंस रिटेल के पास रहेगी। समझौते के तहत दक्षिण एशिया में सुपरड्राई की ब्रांड आईपी संपत्तियां स्थायी रूप से नई संयुक्त उद्यम इकाई को स्थानांतरित कर दी जाएंगी। सुपरड्राई पीएलसी ने कहा कि उसने भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में सुपरड्राई ब्रांड और संबंधित ट्रेडमार्क सहित अपनी बौद्धिक संपदा संपत्तियों की बिक्री के लिए रिलायंस ब्रांड्स होल्डिंग यूके लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

## रियल एस्टेट में मकानों की मांग 6 साल के उच्च स्तर पर

**नईदिल्ली।** रियल एस्टेट उद्योग में बिक्री इस साल भी खूब हो रही है। इस साल की तीसरी तिमाही में मकानों की बिक्री 6 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। तीसरी तिमाही में मकानों की बिक्री में सालाना आधार पर 12 फीसदी इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी महंगे मकानों की बिक्री में हुई है। इस साल की तीसरी तिमाही में नये मकानों की लॉन्चिंग सालाना आधार पर 23 फीसदी बढ़कर 85,549 दर्ज की गई। मकानों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। हैदराबाद में सबसे ज्यादा 11 फीसदी मकान महंगे हुए हैं। इस बीच, तीसरी तिमाही के दौरान आफिस की मांग भी बढ़ी है। रियल एस्टेट सलाहकार फर्म नाइट फ्रैंक इंडिया की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही (जुलाई—सितंबर) में 8 प्रमुख शहरों में 82,612 मकान बिके, जो बीते 6 वर्षों में सबसे अधिक हैं।

# वोकल फॉर लोकल : भारतीय खिलौना उद्योग की किस्मत चमक गई

**डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा**

यदि इच्छाशक्ति हो और कुछ करने की ठान ली जाये तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण है देश का खिलौना उद्योग। यह अभी कल की ही बात लगती है जब भारत 20 हजार करोड़ के खिलौने अकेले चीन से आयात करता था। कोरोना के बाद बदली परिस्थितियों से चीन को लेकर दुनिया के देशों का मोह भंग हुआ और उसके बाद हालात यह होने लगे कि दुनिया के देश चीन और उसकी नीतियों को हिकारत की दृष्टि से देखने लगे। सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया और सरकार के एक आह्वान और सकारात्मक नीतियों का परिणाम यह रहा कि देश में खिलौना उद्योग ने रफ्तार पकड़ी। हालात में तेजी से बदलाव का ही परिणाम है कि आज भारत में खिलौना उद्योग तेजी से फलने-फूलने लगा है।

देशी बाजार में स्वदेशी खिलौनों की मांग बढ़ी तो विदेशी बाजार में भी भारतीय खिलौनों की तेजी से मांग बढ़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें प्रमुख कारण खिलौना उद्योग के लिए प्रोत्साहन नीतियां रहीं। आयात शुल्क बढ़ाने के साथ ही सरकार ने प्रोडक्शन लिंक इंसेटिव स्कीम लागू की जो उद्योग के विकास में सहभागी बनी। आज 12 प्रतिशत विकास दर के साथ खिलौना उद्योग बढ़ रहा है और वह भी चक्रवृद्धि विकास दर है। इसे भारतीय खिलौना उद्योग के लिए शुभसंकेत ही माना जा सकता है।

देखा जाए तो खिलौना उद्योग पर चीन का एकाधिकार ही रहा है। लगभग 80 प्रतिशत बाजार चीन के पास रहा है। ऐसे में चीन के खिलौना उद्योग को चुनौती देना बड़ी मुश्किल भरा काम रहा है। पर एक आह्वान ने सबकुछ बदल कर रख दिया। केन्द्र व राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से देश में

खिलौना उद्योग ने गति पकड़ ली है। एक समय था जब भारत चीन से 20 हजार करोड़ का खिलौना आयात करता था और आज हालात यह हो गए हैं कि भारत में खिलौनों का घरेलू बाजार 124.73 अरब का हो गया है। भारत से खिलौनों के निर्यात में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। 2018-19 में 16.81 करोड़ के खिलौने निर्यात होते थे, 2022-23 में यह बढ़कर 27.08 अरब डॉलर हो गया है। माना जा रहा है कि 2028 तक भारत में खिलौना उद्योग 249.47 अरब रुपये को पार कर जाएगा। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि जो माहौल बना और बनाया गया उसका परिणाम यह रहा कि बच्चों की पहली पसंद भी भारतीय खिलौने ही हो गए हैं।

खिलौना उद्योग में आज 4000 एमएसएमई अपनी भागीदारी निभा रही है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एमएसएमई उद्योग देश का ग्रोथ इंजन होता है। एमएसएमई उद्योगों से जहां रोजगार के अधिक अवसर विकसित होते हैं वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होता है। होता यह है कि बड़े उद्योगों में एक सीमा तक ही रोजगार के अवसर होते हैं क्योंकि वहां तकनीक का अधिक उपयोग होता है तो दूसरी और एमएसएमई उद्योग में रोजगार के अधिक अवसर होने से आर्थिक व्यवस्था को नई दिशा मिलती है। स्थानीय स्तर से लेकर निर्यात तक के अवसर आसानी से उपलब्ध होते हैं। दरअसल सरकार के खिलौनों पर आयात शुल्क 20 से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर देने, कच्चे माल की सहज उपलब्धता, ईज ऑफ डूइंग के तहत आसानी से उद्योगों की स्थापना और इसके साथ ही पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेटिव से उद्योग को बढ़ावा मिला है। इसके साथ ही सरकार द्वारा निर्यात को आसान और आम उद्यमी की पहुँच में करने से देशी विदेशी बाजार मिलने में आसानी हुई है। देश के हस्तशिल्प निर्यात संवर्द्धन परिषद द्वारा भी आवश्यक सहयोग दिया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकारें भी आगे आई हैं और यही कारण है कि बहुत कम समय में देश के खिलौना उद्योग ने देश-विदेश में अपनी पहचान बनाई है। अंत में एक बात और, विदेशों में प्रतिस्पर्धा में बना रहना है तो गुणवत्ता, मूल्य प्रतिस्पर्धा के साथ ही नवाचार और शोध को बढ़ावा देना होगा। सशक्त आरएण्डडी टीम बनानी होगी और इसके साथ बाजार की मांग को भी समझना होगा।

कांग्रेस का विकास देखने दूरबीन लेकर निकले राजेश मूणत, बोले-

# पोस्टर पर दिख रहे हैं 36 हजार करोड़ के काम

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। सभी पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत ने रायपुर पश्चिम विधानसभा में दूरबीन से विकास ढूंढो अभियान की शुरुआत की है। राजेश मूणत समेत बीजेपी के कार्यकर्ता रायपुर के सभी दिशाओं में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए विकासकार्यों को ढूंढने निकले। यह अभियान पूरे रायपुर पश्चिम विधानसभा में चलाया गया है। इस दौरान राजेश मूणत के साथ सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने दूरबीन लेकर रायपुर पश्चिम का भ्रमण करते हुए %अउ नहीं सहिबो, बदल के रहिबो% के नारे भी लगाए।

राजेश मूणत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम एक शासकीय भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान हास्यास्पद बयान और झूठ बोले थे। सीएम ने कहा था कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में रायपुर शहर में बीते तीन महीनों में हुआ विकास कार्य भाजपा के 15 साल के कार्यकाल से अधिक है। इस बात पर राजेश मूणत ने बघेल को उनके साथ रायपुर पश्चिम विधानसभा का दौरा करने का न्योता देते हुए कहा था कि अगर भूपेश बघेल की बात सही है, तो वह साथ चलकर कांग्रेस शासनकाल के विकासकार्यों को दिखाएं।




मूणत ने कहा कि बीते 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अनगिनत स्वर्णिम विकास के कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के लोक निर्माण विभाग का मंत्री रहते हुए स्वयं रायपुर शहर में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण प्राथमिकता लेकर और हर क्षेत्र के उत्थान में भेदभाव पूर्ण जनहित का कार्य किया है। मूणत ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में शहर को अपराध गढ़ और खोदापुर बनाने के सिवाय कोई दूसरा काम नहीं हुआ है। मूणत ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल ने उनका आमंत्रण स्वीकार ना करके अपना झूठ स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि दूरबीन के माध्यम से कांग्रेस के शासनकाल में हुए विकास ढूंढने की कोशिश किए जो कि असफल साबित हुई है।

राजेश मूणत ने कहा कि हम भूपेश बघेल के दावों के सच जानने बीते तीन महीने में 36 हजार करोड़ के काम को ढूंढने निकले थे। इस दौरान हमें कांग्रेस का एक भी विकास कार्य नहीं दिखा। केवल विज्ञापनों, होर्डिंग, पोस्टर में छपी कांग्रेस नेताओं की तस्वीरों में ही विकास दिखाई दिया। मूणत ने कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि उन्हें नाम वाला नहीं, बल्कि काम वाला विकास चाहिए। आने वाले चुनाव में रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के खिलाफ मतदान करके भूपेश को सबक सिखाएंगी नदेश दिए। साथ ही उपलब्धियों की जानकारी ली।

# झूठ की बुनियाद पर खड़ी है कांग्रेसः अजय चंद्राकर

**रायपुर।** भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता पहले अपने गिरेबाँ में झाँकें। सच यह है कि पूरी कांग्रेस पार्टी झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। श्री चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेसी झूठ और भ्रम फैलाने में माहिर हैं। भाजपा मुख्य प्रवक्ता व पूर्व मंत्री श्री चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस हर बार झूठ बोल कर सत्ता में आती है और जनता के साथ धोखाधड़ी करती है। करप्शन और कमीशन का खुला खेल खेलती है। दूसरी ओर भाजपा जो कहती है वह पूरा करके दिखाती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब संसद या खुले मंच पर सवाल करते हैं तो कांग्रेसी निरुत्तर होकर जवाब नहीं दे पाते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा धान और वनोपज खरीदी को लेकर झूठ बोलने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पहले भूपेश सरकार बताए कि क्या केंद्र सरकार धान खरीदी के लिये पैसे नहीं देती? श्री चंद्राकर ने कहा कि 2018 के चुनावी घोषणा-पत्र में कांग्रेस द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों को दो साल का बकाया बोनस देने की बात कही गई थी। आखिर दो साल का बोनस किसानों को क्यों नहीं दिया? 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, वह भी झूठ निकली। भूपेश सरकार बताये कि कितने बेरोजगारों को रोजगार



दिया गया? चुनाव करीब आते आते बेरोजगारी भत्ता देने की शुरुवात की। वह भी जटिल शर्तों व मापदंडों के साथ जिसके कारण कई बेरोजगारों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। भाजपा मुख्य प्रवक्ता व पूर्व मंत्री श्री चंद्राकर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी पर ओबीसी, अजा, अजजा के साथ भेदभाव करने के आरोप को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि वास्तविकता क्या है, यह जनता के सामने है। कांग्रेस नेताओं को भारत के इतिहास को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। इतिहास गवाह है कि हिन्दू-मुस्लिम करके वैमनस्यता फैलाने का काम कांग्रेस ही करती आई है। मुस्लिमों को वोट बैंक समझने वाली कांग्रेस की सच्चाई मुस्लिम समुदाय भी अब भलीभाँति जान चुका है। केंद्र सरकार का तो मूलमंत्र ही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। श्री चंद्राकर ने पिछले 70 सालों से बस्तर को छलने और अंधेरे में रखने वाली कांग्रेस सरकार भाजपा के 15 साल के सुशासन और बस्तर के आदिवासियों का विकास देखकर तिलमिलाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही है। जब बस्तर के लोगों के सर्वांगीण विकास करने का प्रधानमंत्री श्री मोदी ने संकल्प लेने की बात कही, तो कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज अनर्गल, झूठे आरोप लगाकर छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

# दो करोड़ तीन लाख 60 हजार 240 मतदाता करेंगे मतदान

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर बुधवार को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने अंतिम मतदाता सूची जारी करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में दो करोड़ तीन लाख 60 हजार 240 मतदाता मतदान करेंगे।

छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में पत्रकार-वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार-वार्ता में बताया कि प्रदेश में निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद आज सभी मतदान केंद्रों




में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। आज प्रकाशित सूची के अनुसार राज्य में कुल दो करोड़ तीन लाख 60 हजार 240 मतदाता हैं। इनमें एक करोड़ एक लाख 20 हजार 830 पुरुष मतदाता, एक करोड़ दो लाख 39 हजार 410 महिला मतदाता और 790 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद राज्य में सात लाख 19 हजार 825 मतदाता बढ़े हैं। इससे पहले 28 सितंबर तक दावा आपत्तियों का निराकरण किया गया।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर और श्री बिपिन माझी सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी पत्रकार-वार्ता में मौजूद थे।

# सांसद सोनी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय योजनाओं की हुई समीक्षा

**रायपुर।** सांसद सुनील सोनी के अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक हुई। रायपुर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे, नगर निगम आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अबिनाश मिश्रा, उपस्थित थे।

बैठक में सांसद श्री सोनी ने संबोधित करते हुए कहा कि इस बैठक का उद्देश्य जनता को शासकीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ देना है इसलिए बैठक में शामिल जनप्रतिनिधि अपनी क्षेत्र की समस्याओं के बारे में निशंकोच अधिकारियों के सामने अपनी बात रखें, जिससे वास्तविक जानकारी सामने आए और समस्या का समाधान हो। जिले के सभी अधिकारियों को योजनाओं के तहत मंजूर किए गए कामों की सतत मॉनिटरिंग-समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजनों की सहूलियत के लिए स्वीकृत किए गए विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए लगातार समीक्षा की जानी चाहिए।

श्री सोनी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि संबंधित विभाग सड़कों की मरम्मत करें।

जलजीवन मिशन की तहत दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर और गुणवत्तापूर्ण कार्य करें। राजधानी में दशहरा, दीपावली तथा अन्य त्योहार आने वाले हैं। सड़कों एवं प्रमुख बाजारों में भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होगी, उससे पहले नगर निगम शहर की सड़कों का सुधार करें और साफ सफाई में विशेष ध्यान दें। सांसद आदर्श ग्राम में मूलभूत सुविधाओं का मुहैया कराएं।

# पॉवर कंपनी में डाटा एंट्री आपरेटर एवं परिचारक के 785 पदों के लिए होगी भर्ती

■ **एक महीने में 1200 से अधिक पदों के लिये जारी हुए भर्ती विज्ञापन**

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी में डाटा एंट्री आपरेटर और परिचारक श्रेणी-3 (संयंत्र) के 785 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए भर्ती विज्ञापन जारी कर दिये गए हैं। इस तरह एक महीने में पॉवर कंपनी ने 1200 से अधिक नियमित पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किये हैं। इन सभी पदों के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल परीक्षा लेगा।

भूपेश बघेल एवं माननीय उपमुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश के युवाओं के लिए रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती के निर्देश दिए थे, जिसके पालनार्थ पॉवर कंपनी ने पहले एई और जेई के कुल 429 पद तथा अब डाटा एंट्री आपरेटर



और परिचारक श्रेणी-03 (संयंत्र)के कुल 785 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी कर दिये हैं। इस तरह पॉवर कंपनी में 1200 से अधिक नियमित पदों पर भर्ती हो रही है।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) श्री अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि डाटा एंट्री आपरेटर के 285 पद एवं परिचारक श्रेणी-03 (संयंत्र) के 500 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें डाटा एंट्री आपरेटर के लिए ट्रांसमिशन कंपनी के 104 पद एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में 181 पद हैं। इसी तरह जनरेशन कंपनी में परिचारक श्रेणी-03 (संयंत्र)के 500 पदों में भर्ती की जाएगी।

श्री वर्मा ने बताया कि जनरेशन कंपनी में परिचारक श्रेणी-03 (संयंत्र) के लिए विद्युतकार, फीटर, टर्नर, इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक एवं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड पर भर्ती होगी।

भर्ती प्रक्रिया के साथ वांछित अर्हता, आयुसीमा, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया आदि शर्तों की विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी की वेबसाइट 222.प्बहंकण्छण्ळ्ट तथा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) की वेबसाइट www.cgvyapam.choice.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन व्यापमं की वेबसाइट पर आमंत्रित किये गए हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

## नगरनार संयंत्र के निजीकरण पक्ष में जनता विरोध में : बैज

**रायपुर।** प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि भाजपा नगरनार संयंत्र की निजीकरण की पक्षधर है। इस लिये बस्तर की जनता की भावनाओं के विपरीत बयानबाजी कर निजीकरण को सही ठहराने की कोशिश कर रही हो लेकिन नगरनार संयंत्र की निजीकरण के विरोध में किसान, आदिवासी, युवा व्यापारी, महिलाओं ने बस्तर को स्वस्फूर्त बंद कर मोदी सरकार की निजीकरण का विरोध किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बस्तर आये लेकिन नगरनार संयंत्र की निजीकरण पर स्पष्ट जवाब नहीं दिये। बल्कि हमेशा की तरह झूठ बोलकर गोलमोल जवाब देकर निजीकरण का बचाव करते रहे है। बस्तर के आदिवासियों ने अपनी जमीन एनएमडीसी के नगरनार स्टील प्लांट को दी थी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के जरिए इस जमीन का मकसद बस्तर का विकास था। नगरनार स्टील प्लांट को विनिवेश सूची में डाले जाने पर मजदूर संगठनों, किसानों में भारी नाराजगी दिखाई थी। इसके विरोध में वर्तमान मुख्यमंत्री और तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के नेतृत्व में विशाल पदयात्रा निकाली गई। जिसमें 10 ग्राम पंचायत के प्रभावित किसान, 12 गांवों के हितग्राही और संयुक्त मजदूर किसान संगठन, स्टील श्रमिक यूनियन भी शामिल थे। कांग्रेस की ओर से सरकार बनने से पहले विधानसभा अशासकीय संकल्प लाया गया था।

## सिपहसालार बनना खड़गे को शोभा नहीं देताः सरोज पांडेय

**रायपुर।** भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद डॉ. सरोज पांडेय ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा रायगढ़ में आयोजित शासकीय कार्यक्रम में राजनीतिक बातें कहे जाने का कड़ा प्रतिवाद करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे पर कांग्रेस की जो महफिलें सजाई जा रही हैं और उनमें जिस निम्न स्तर की टिप्पणियां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वह जनता देख रही है कि कैसे पैसे का किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है। झूठों के सरदार के सिपहसालार बनना खड़गे को शोभा नहीं देता। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर बात गारंटी होती है। झूठों के सरदार तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और उनसे भी बड़े झूठे राहुल गांधी हैं, जो घूम घूम कर भूपेश के झूठों का प्रचार करते हुए उनके ब्रांड एंबेसडर बने हुए हैं। क्योंकि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की जनता को लूट लूट कर कांग्रेस का खजाना भर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता के धन की बर्बादी करके कांग्रेस अगर यह सोचती है कि जनता उसके झूठे प्रचार पर भरोसा कर लेगी तो कांग्रेस को यह गलतफहमी मुबारक हो। छत्तीसगढ़ की जनता को भूपेश सरकार पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। इसलिए वह भरोसे के सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के आयोजनों को सरकारी कार्यक्रम का रूप दिया जा रहा है। यदि यह सरकारी कार्यक्रम हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे इनमें राजनीतिक बातें कैसे कर रहे हैं? मां-बेटे की सरकार तो मनमोहन सिंह के जमाने में चला करती थी।

## प्रधानमंत्री चार बार छत्तीसगढ़ आये चार बड़े झूठ बोलेः ठाकुर

**रायपुर।** भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक अजय चंद्राकर के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कुछ महीनो में चार बार छत्तीसगढ़ आये हैं और चार बड़े झूठ बोले जिसे प्रदेश की जनता ने पकड़ लिया, प्रधानमंत्री के झूठ पकड़ाने के बाद भाजपा तिलमिला रही है। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा की जा रही धान को केंद्र द्वारा खरीदना बताकर झूठ बोले, जबकि राज्य सरकार बैंको से कर्ज लेकर धान की खरीदी करती है। जी-20 कार्यक्रम सम्पन्न होना बताकर झूठ फैलाई जबकि उस समय जी-20 कार्यक्रम हुआ ही नहीं था। पूर्व से चली आ रही परियोजनाएं और शुरू हो चुकी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके सौगात देने का भ्रम फैलाई, अभी बस्तर में नगरनार संयंत्र के निजीकरण के विषय में गोल-गोल जवाब देकर बस्तर की जनता को धोखा दिया, जातिगत जनगणना के विषय पर भ्रम फैलाई पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर झूठे आरोप लगाए। और अनेक कई मामलों में झूठ परोसे हैं। भाजपा नेताओं का सभाओं में भीड़ के आगे झूठ बोलना संगामक गुण हैं। भाजपा नेताओं को नरेंद्र मोदी के झूठ पकड़ाने के बाद शर्म आना चाहिए। लेकिन भाजपा की सदस्यता की पहली शर्त झूठ बोलना बार बार बोलना झुंड बनाकर बोलना है।

## कांग्रेस राज में बच्चियों को नीट, आईआईटी की मुफ्त कोचिंग मिल रही हैः शुक्ला

**रायपुर।** मुख्यमंत्री द्वारा आईना दिखाने पर भाजपा तिलमिला गई है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रमन राज में छत्तीसगढ़ में आदिवासी बच्चियों को शराब परोसने की ट्रेनिंग दी जाती थी। आज छत्तीसगढ़ के बच्चियों को नीट, आईआईटी की कोचिंग दी जा रही है। यह फर्क है भाजपा और कांग्रेस के राज में, कांग्रेस सरकार बच्चियों के उज्जवल भविष्य के लिये योजना बनाकर क्रियान्वयन कर रही। भाजपा बच्चियों को बार बाला बना रही थी। भाजपा को तो अपने कृत्य के लिये प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिये। उस समय भी कांग्रेस ने बच्चियों को शराब परोसने की ट्रेनिंग देने की आलोचना करते हुये विरोध किया था। कांग्रेस की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में शराब की खपत में कमी आई है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रमन सरकार ने छत्तीसगढ़ में शराब का सरकारीकरण कर प्रदेश में शराब की खपत को बढ़ावा दिया। भाजपा सरकार का उद्देश्य शराब से राजस्व को बढ़ाकर ज्यादा मुनाफा कमाना था। राज्य में शराब की खपत कम करने कांग्रेस सरकार ने 100 से अधिक शराब दुकानों को बंद किया। आज छत्तीसगढ़ में 2018 की अपेक्षा अंग्रेजी शराब की खपत में 15 फीसदी और देशी शराब की खपत में 10 प्रतिशत की कमी आई है।

## 48 वें निःशुल्क नियमित योगाभ्यास केंद्र का शुभारंभ

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा रायपुर के शंकर नगर स्थित बालाजी उद्यान में 48 वें निःशुल्क नियमित योगाभ्यास केन्द्र का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा तथा छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा रहे। योगाभ्यास केन्द्र का संचालन योग प्रशिक्षक श्री प्रदीप साहू द्वारा प्रतिदिन सुबह 06 से 07.30 बजे तक किया जाएगा गौरतलब है कि बीते 30 सितंबर को अग्रसेन चौक रायपुर में 47 वें निःशुल्क नियमित योगाभ्यास केन्द्र का शुभारंभ श्री ज्ञानेश शर्मा के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस प्रकार योग आयोग द्वारा राजधानी रायपुर में लगातार निःशुल्क योगाभ्यास केन्द्र खोले जा रहे हैं, जिनका लाभ आमजनता को मिल रहा है। श्री ज्ञानेश शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा प्रदेश में आमजनों के स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के लिए निरन्तर निःशुल्क नियमित योगाभ्यास केंद्र का प्रारंभ किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पूरे विश्व पहचाना जा सके इसके लिए हम सदैव तत्पर हैं। श्री कुलदीप जुनेजा ने कहा कि छत्तीसगढ़ योग आयोग राज्य के आमजनों को शारीरिक और मानसिक रूप स्वस्थ रखने का महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में वार्ड के पार्षद श्री अमितेश भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में योग साधकगण उपस्थित रहे।



# सत्य के रास्ते में चलने का संदेश बाबा गुरु घासीदास जी का हैः भूपेश बघेल

**रायगढ़।** मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में कहा कि, कला और संस्कृति के मुख्यालय हमारे रायगढ़ में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने के बाद खड़के की सबसे पहले रायपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन में आए। तबसे उनका लगाव छत्तीसगढ़ में बना रहा है। अभी हमारे मुख्य अतिथि खड़गे जी के हाथों से बाबा गुरु घासीदास जी के आस्था के प्रतीक और गांव-गांव में निर्मित जैतखाम का शिलान्यास हुआ। सत्य के रास्ते में चलने का संदेश बाबा गुरु घासीदास जी का है। सत्य के रास्ते को महात्मा गांधी जी ने भी बताया। सत्य का रास्ता हमारा रास्ता है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव जी, नरसिम्हा राव जी सभी का उद्देश्य हिंदुस्तान की जनता को ताकतवर बनाने का रहा। हमारा एक ही उद्देश्य रहा है कि कैसे आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सके, महिलाओं के जीवन में कैसे परिवर्तन लाया जा सके। हमारे सुदूर वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी भाइयों बहनों को आर्थिक रूप से



मजबूत बनाने के लिए लघु वनोपज खरीदने की व्यवस्था हमने हर जगह की, धान खरीदी की व्यवस्था हो रही है। देश का तीन चौथाई लघुवनोपज छत्तीसगढ़ में खरीदा जाता है। हमने शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से बीमा योजना शुरू की जिसका लाभ 12.50 लाख संग्राहकों को मिल रहा है। ये छत्तीसगढ़ मॉडल है, जिसमें सबसे किया वायदा हम निभाते हैं। समर्थन मूल्य में धान खरीदी, भूमिहीन मजदूरों को 7 हजार रुपए प्रतिवर्ष आर्थिक अनुदान, अंग्रेजी माध्यम में निःशुल्क शिक्षा देने का वायदा था, हमने दिया। आज छत्तीसगढ़ में किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं, बच्चे सभी को मजबूत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार आपका पैसा आप तक लौटा रही है। हमारी सरकार संसाधनों का उपयोग आपके हित में करती है। आवास बनवाने के लिए हमने 47 हजार परिवार के खातों में 25-25 हजार रुपए की राशि जमा करवा दी। हमने आर्थिक सर्वेक्षण करवाया इसकी रिपोर्ट में जो आया उसके हिसाब से हमने तय किया है कि अब 10 लाख आवासहीन परिवारों को आवास देकर रहेंगी।

# चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों को दिये निर्देश

**रायपुर।** मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आगामी विधानसभा चुनाव संबंध में अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अधिकारियों को आगामी विधानसभा चुनाव में आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक निर्देश दिये गये है। आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान केन्द्रीय सशक्त पुलिस बल तैनात किये जायेंगे इनके लिए सभी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे आवास, परिवहन, राशन, पेयजल जलपूर्ति, स्वास्थ्य दवाई, इलाज, मोबाईल, टायलेट, बांस बल्ली सहित अन्य आवश्यकताओं



के लिए विभिन्न विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये है।

बैठक में बताया गया कि विधानसभा चुनाव हेतु सी.ए.पी.एफ की करीब 150 कम्पनियों का शीघ्र ही छत्तीसगढ़ आगमन होगा। विधानसभा चुनाव हेतु अधिकारियों ने होम गार्ड की उपलब्धता के बारे में बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों के करीब 6996 होम गार्ड बल उपलब्ध है। इनमें से करीब 3115 होम गार्ड की ड्यूटी विधानसभा चुनाव में लगायी जायेंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस में आयोजित इस बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी पिल्ले, सचिव शिक्षा डॉ. एस. भारती दासन, गृह विभाग के सचिव श्री अरूण देव गौतम, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव एन.एन.एक्का, खाद्य विभाग के सचिव श्री टोपेश्वर वर्मा सहित परिवहन, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वन, नगरीय प्रशासन तथा ऊर्जा विभाग सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मिडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.